

अडानी एमएससी विडिंजम पोर्ट डील के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी: सीएम सतीशन

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। मुख्यमंत्री की डी सतीशन ने कहा कि अडानी ग्रुप के विडिंजम पोर्ट के 49 प्रतिशत शेयर स्विट्जरलैंड की मेडिटरेनियन शिपिंग कंपनी को ट्रांसफर करने के कदम के लिए राज्य सरकार की पहले से मंजूरी जरूरी है. विधानसभा में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन की एक अजीब और जैविक चिट्ठिलापिल्ली के एक सवाल का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने साफ किया कि हालांकि सरकार को रिपोर्ट के बारे में पता है, लेकिन अडानी ग्रुप ने न तो उनसे संपर्क किया है और न ही अभी तक इजाजत मांगी है. यूरोप की बड़ी शिपिंग कंपनी एमएससी, अडानी विडिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के लगभग आधे शेयर खरीद रही है. एमएससी, कंपनी में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी 1.397 बिलियन डॉलर, लगभग 13270 करोड़ रुपये में खरीद रही है, जिसकी अनुमानित वैल्यूएशन 2.85 बिलियन डॉलर, लगभग 27000 करोड़ रुपये है. एमएससी के पोर्ट ऑपरेटिंग डिवीजन टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की सॉफिसिडरी



मुंडी लिमिटेड, शेयर ले रही है. केरल और भारतीय पोर्ट सेक्टर में सबसे बड़े विदेशी निवेश को दिखाते हुए, इस डील में टीटीएल शामिल हुई है, जो पांच महाद्वीपों में 100 से ज्यादा कंटेनर टर्मिनल चलाती है और जिसकी सालाना कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 70 मिलियन टीईयूएस (बीस फुट समतुल्य इकाई) से ज्यादा है. गुजरात के मुंद्रा पोर्ट और तमिलनाडु के एन्नोर पोर्ट पर उनकी पार्टनरशिप के बाद,

यह भारत में अडानी ग्रुप और एमएससी के बीच तीसरा सहयोग है. समझौते की शर्तों के मुताबिक, अडानी ग्रुप राज्य सरकार की मंजूरी के बिना स्वामित्व संरचना में बदलाव नहीं कर सकता. चूंकि पोर्ट 2080 में पूरी तरह से राज्य सरकार को सौंप दिया जाना है, इसलिए बड़े विदेशी निवेश के बारे में कोई भी बातचीत तभी आगे बढ़ सकती है जब सरकार इस प्रक्रिया में सक्रिय पार्टनर हो. क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे

जरूरी है, इसलिए डील के लिए केंद्रीय शिपिंग और गृह मंत्रालयों से मंजूरी भी जरूरी है. मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक हित, प्रतिस्पर्धी तरीकों, निवेश को बढ़ावा देने, दूर की सोचने वाले लक्ष्यों और राज्य के राजस्व हितों को सुरक्षित रखते हुए ही अडानी एमएससी समझौते को मंजूरी देगी. विडिंजम पोर्ट पर विकास गतिविधियों का दूसरा चरण अभी तेजी से चल रहा है. इस फैसिलिटी की अभी कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी 1.6 मिलियन ट्वेंटी फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स है. दिसंबर 2028 तक विकास का काम पूरा होने की उम्मीद है, और यह कैपेसिटी साढ़े तीन गुना बढ़कर 5.7 मिलियन टीईयूएस तक पहुंचने का अनुमान है. एमएससी के साथ सहयोग से विडिंजम में ज्यादा कंटेनर आने में आसानी होगी और आधारभूत संरचना में काफी सुधार होगा, ब्रिटिश जमाने के नेवो इतिहास के साथ-साथ ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर पोर्ट की जगह पक्की हो जाएगी. विधायक साजी चेरियन के

एक सवाल का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पोर्ट बनने से बेघर हुए और प्रभावित हुए लोगों के लिए एक खास पुनर्वास पैकेज लागू किया जाएगा. अभी एक या दो सेंट के तम प्लॉट में रहने वाले मछुआरों को अच्छी सुविधाओं वाले फ्लैट या घर दिए जाएंगे. ये कोशिशें ओमन चांडी सरकार के समय में घोषित 475 करोड़ रुपये के पुनर्वास पैकेज के आधार पर आगे बढ़ रही हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की नीति जलवायु परिवर्तन और समुद्री कटाव के असर से परेशान तटीय समुदायों को मजबूती से समर्थन करना है. विधायक नजीब कंथापुरम के एक सवाल का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि विडिंजम पोर्ट को एकेडमिक सेक्टर से जोड़ने के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मैरिटाइम म्यूजियम बनाया जाएगा. यह म्यूजियम नई पीढ़ी को पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश जमाने के नेवो इतिहास के साथ-साथ कुंजली मरक्कर की महान लड़ाई की भावना के बारे में बताने का काम करेगा।

विभाजन के बाद भारत आने वाले लोग शरणार्थी नहीं, बल्कि योद्धा थे

मोहन भागवत ने विस्थापितों के संघर्ष को सराहा

नागपुर, एजेंसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि 1947 के विभाजन के बाद भारत आने वाले लोग शरणार्थी नहीं थे, बल्कि ‘संघर्ष के योद्धा’ थे जिन्होंने मातृभूमि और धर्म के प्रति प्रेम के कारण कठिनाइयाँ और दर्द को झेला। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पाकिस्तान में अपनी संपत्ति और व्यवसाय छोड़कर भारत आने का निर्णय लिया। भागवत नागपुर में सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के 75वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस सोसाइटी का संचालन सिंधी समाज की ओर से किया जाता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि विभाजन के बाद इन लोगों ने जानबूझकर भारत आने का निर्णय लिया, क्योंकि वे उस भूमि में रहना चाहते थे जहां वे बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सकें। उन्होंने कहा- ‘वे शरणार्थी नहीं थे, हालांकि वे विस्थापित थे। वे योद्धा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम के चलते कष्ट झेला। उन्होंने करियर या धन नहीं, बल्कि देश और धर्म को चुना।’ जीवन की कठिनाइयों पर उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए किसी को हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि फिर से उठने का प्रयास करना चाहिए। अंततः सफल भी वही होता है।

उन्होंने सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की 75

दिल्ली में मानसून की दस्तक: सूपी में वज्रपात से आठ लोगों की मौत, एनसीआर समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

लखनऊ, एजेंसी। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, जिसके चलते कहीं राहत तो कहीं भीषण आफत देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक दे चुका है। वहीं, पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली (वज्रपात) गिरने के कारण अलग-अलग जिलों में आठ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बुधवार को प्रदेश भर मानसून की दस्तक से जहां राहत महसूस की गई, वहीं वज्रपात व घर गिरने से आठ लोगों की मौत हो गई। सुलतानपुर व मुरादाबाद में चार लोगों की मौत धान की रोपाई करते हुए हुई। बलिया में दो लोगों की वज्रपात से मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से झुलसा है। एक अन्य घटना में ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने वाले व्यक्ति की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। वाराणसी में भी वज्रपात से एक मौत व्यक्ति की मौत की सूचना है। अलीगढ़ में छज्जा गिरने से एक वृद्ध गायब हो गई। यहां सीढ़ियों के मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। काफी इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अत्यधिक मौसमी परिस्थितियों के कारण मानसून आज दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। राजधानी और आसपास के इलाकों (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद) में सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो चुका है।

इन राज्यों में अलर्ट जारी: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और पूर्वी राजस्थान में अत्यधिक भारी बारिश का ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया है, जहां भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भी मानसून पूरी तरह सक्रिय है, जिसके चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। कोकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के कारण दिल्ली-एनसीआर समेत बड़े शहरों में जलभराव हो सकता है, जिससे सुबह और शाम के पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है।

फुटपाथ पर चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं’, हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि फुटपाथ पर सुरक्षित तरीके से चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। पैदल लोगों के लिए बनाए गए फुटपाथों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने लुधियाना नगर निगम को शहर के फुटपाथों पर अतिक्रमण की शिकायतों की तत्काल जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने यह आदेश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका लुधियाना के जसबीर सिंह ने दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि शहर में फुटपाथों की हालत बेहद खराब है और बड़ी संख्या में उन पर अतिक्रमण हो चुका है, जिससे लोगों को मजबूरन व्यस्त सड़कों पर चलना पड़ता है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि सितंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच नगर निगम और अन्य संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायतें और ज्ञापन दिए गए, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। फुटपाथों पर रेड्डी-फडी वालों और अन्य अवैध कब्जों के कारण पैदल चलना मुश्किल हो गया है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया।

अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत, उपराज्यपाल ने जम्मू से पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना



जम्मू, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को जम्मू से श्री अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इसके साथ ही, इस सालाना यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के जत्थे को रवाना करने से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सांसद जुगल किशोर शर्मा, जम्मू-कश्मीर के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा और भाजपा विधायक अरविंद गुप्ता मौजूद रहे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘हर-हर महादेव। बाबा बर्फानी के पवित्र धाम की यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। जम्मू के भगवती नगर बस कैप से श्री

अमरनाथ यात्रा 2026 के श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ‘उन्होंने आगे लिखा, ‘श्री अमरनाथ जी की यात्रा एक आध्यात्मिक जागृति है। इस पवित्र रास्ते पर उठाय गया हर कदम बाबा अमरनाथ के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण का प्रमाण है। सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित, मंगलमय और आध्यात्मिक आनंद से परिपूर्ण हो, ऐसी कामना है। भगवान शिव हम सभी पर कृपा बनाए रखें।’ भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने समाचार एजेंसी आईएनएस से बात करते हुए कहा, ‘इस बार यात्रा में पहले से अधिक तीर्थयात्रियों की संख्या नजर आती है। यहां व्यवस्थाओं की भी कोई कमी नहीं है। प्रशासन ने सभी

व्यवस्थाएं की हैं। खासकर नगर निगम, पर्यटन विभाग, पुलिस और कई अन्य सरकारी एजेंसियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात काम किया है कि श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं। ‘ उन्होंने कहा कि देशभर से श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही, भाजपा सांसद ने कहा, ‘ मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि वे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आएँ और उनका आशीर्वाद लें। ‘ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि तीर्थयात्रियों में अमरनाथ यात्रा को लेकर जोश और उत्साह है। आज पहला जत्था रवाना हुआ है। 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के लिए हम बाबा बर्फानी से कामना करते हैं कि देश के अनेक प्रांतों से आए हुए श्रद्धालुओं की यात्रा को सुखद और सफल बनाएं। सुनील शर्मा ने कहा कि अमरनाथ यात्रा बहुत ही अनोखी यात्रा है। पूरे विश्व में इस तरह की यात्रा कहीं और नहीं है। इस धरती पर यह एक पवित्र स्थान है, जहां बाबा बर्फानी साक्षात दर्शन देते हैं। भाजपा विधायक अरविंद गुप्ता ने कहा, ‘यह मेरे लिए गौरव का पल है कि मुझे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ अमरनाथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला। इस यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में

वया पनामा नहर पर कब्जा कर रहा चीन ट्रंप ने दी खुली चेतावनी, बोले- ऐसा कभी नहीं होने देंगे

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर पनामा नहर और चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पनामा नहर का नियंत्रण सौंपकर बड़ी गलती की थी और अब चीन इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। उन्होंने यह बयान नॉर्थ डकोटा में थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह के दौरान दिया। इस दौरान उन्होंने जन्मसिद्ध नागरिकता और राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी अपनी राय रखी। ट्रंप ने कहा कि जब अमेरिका ने पनामा नहर का नियंत्रण पनामा को सौंपा तो उसके बाद वहां से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क कई गुना बढ़ा दिया गया। उनके अनुसार, इससे पनामा को भारी आर्थिक फायदा हुआ। ट्रंप ने दावा किया कि अब चीन इस अहम समुद्री मार्ग पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने रणनीतिक हितों से जुड़ा यह मुद्दा किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं करेगा।

पनामा नहर को लेकर चीन पर क्यों साधा निशाना: ट्रंप ने कहा कि पनामा नहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। उनका दावा है कि चीन इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन को पनामा नहर पर नियंत्रण या प्रभाव स्थापित नहीं करने देगा। उन्होंने पनामा नहर का नियंत्रण पनामा को सौंपने के पुराने फैसले की ओर बतवाया। ट्रंप के अनुसार, नियंत्रण मिलने के बाद पनामा ने जहाजों से वसूले जाने वाले ट्रांजिट शुल्क में कई बार बढ़ोतरी की। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका के हितों को नुकसान हुआ और पनामा को आर्थिक फायदा मिला।

अमेरिका फर्स्ट ही भविष्य : आजादी की 250वीं वर्षगांठ से पहले ट्रंप ने और वया कहा रूजवेल्ट का भी किया जिक्र

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका अपनी आजादी की 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने देशवासियों को एक बड़ा राजनीतिक और वैचारिक संदेश दिया है। नॉर्थ डकोटा में थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह में ट्रंप ने कहा कि सरकार का पहला कर्तव्य केवल अमेरिकी लोगों की सेवा करना है और यही ‘अमेरिका फर्स्ट’ की असली भावना है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के जीवन और विचारों को अमेरिका के भविष्य के लिए प्रेरणा बताया। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका के 250वें वर्ष में देश को अपने इतिहास, साहस और राष्ट्रभक्ति को फिर से याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक ऐतिहासिक और वीर राष्ट्र है, जिसने हमेशा कठिन



परिस्थितियों का सामना किया है। ट्रंप ने कहा कि थियोडोर रूजवेल्ट ने कभी हार नहीं मानी और वही जज्बा आज के अमेरिका को भी अपनाता चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता, साहस और राष्ट्रिय हित किसी भी मजबूत राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होते हैं।

'अमेरिका फर्स्ट' क्यों बताया

सबसे बड़ी प्राथमिकता: ट्रंप ने कहा कि यदि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा का आज भी कोई अर्थ है, तो वह यही है कि सरकार केवल अमेरिकी जनता के हित में काम करे। उन्होंने कहा कि ‘अमेरिका फर्स्ट’ कोई नारा नहीं, बल्कि शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। ट्रंप के अनुसार, राष्ट्रीय हित को दलगत राजनीति, विशेष वर्षगांठ को केवल एक ऐतिहासिक आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मविश्वास को मजबूत करने का अवसर बताया। उन्होंने कहा कि यह समय उस अदम्य भावना को फिर से अपनाने का है, जिसने अमेरिका को दुनिया की प्रमुख शक्तियों में शामिल किया। थियोडोर रूजवेल्ट ऐसे नेता थे, जिन्होंने ट्रंप ने कहा कि देश को महत्वाकांक्षा, साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने रूजवेल्ट के उस विचार का भी उल्लेख किया,

जिसमें कहा गया था कि कार्यों के हाथों में स्वतंत्रता लंबे समय तक नहीं टिक सकती। ट्रंप ने कहा कि रूजवेल्ट ने देश के विकास, पर्यावरण संरक्षण, श्रमिकों के हित और राष्ट्रीय एकता के लिए काम किया।

वया 250वीं वर्षगांठ को ट्रंप राजनीतिक संदेश से जोड़ रहे हैं ट्रंप अपने भाषण में ट्रंप ने अमेरिका की 250वीं हित वर्षगांठ को केवल एक ऐतिहासिक आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मविश्वास को मजबूत करने का अवसर बताया। उन्होंने कहा कि यह समय उस अदम्य भावना को फिर से अपनाने का है, जिसने अमेरिका को दुनिया की प्रमुख शक्तियों में शामिल किया। थियोडोर रूजवेल्ट ऐसे नेता थे, जिन्होंने ट्रंप ने कहा कि देश को महत्वाकांक्षा, साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा ताकि भविष्य की चुनौतियों का मजबूती से सामना किया जा सके।

रूजवेल्ट को कम्युनिज्म का विरोधी बताकर वया संदेश दिया

ट्रंप ने थियोडोर रूजवेल्ट को कम्युनिज्म का कट्टर विरोधी बताते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी विचारधाराओं के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई थी, जो सभ्यता और स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकती हैं।

ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका की ताकत उसकी स्वतंत्र सोच, लोकतांत्रिक व्यवस्था और बड़े लक्ष्य हासिल करने की महत्वाकांक्षा में निहित है। उन्होंने कहा कि देश को आगे भी इन्हीं मूल्यों के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

कतर की मध्यस्थता रंग लाई: दोहा में र-ईरान वार्ता से बढ़ी उम्मीद, 14 सूत्रीय समझौते पर हुई सकारात्मक चर्चा

दोहा, एजेंसी। कतर के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार कतर और पाकिस्तान ने दोहा में अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों के साथ अलग-अलग बैठकों संपन्न कीं। जिनमें 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) से संबंधित मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई।



प्रधानमंत्री के सलाहकार ने क्या बताया: गुरुवार को एक एक्स पोस्ट में कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार और विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता माजेद अल अलमानी ने कहा कि वार्ता लेक ल्यूसर्न शिखर सम्मेलन के परिणामों पर आधारित थी। यह ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता के अंतिम यात्रा के बाद जारी रहेगी।

बैठक में क्या हुआ: तत्समीन न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान के कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजेम रारीबाबानी ने कहा ‘हमने दोहा बैठक में लेबनान में प्रतिबद्धताओं

अधिकारी पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की अंतिम यात्रा 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक के अलग- अलग स्थानों पर करने की योजना है। बता दें कि खामेनेई की मृत्यु 28 फरवरी को ईरान के साथ अमेरिका-इराक युद्ध के पहले दिन एक हवाई हमले में हुई थी। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण अच्छी तरह चल रहा है। कतर में बरिष्ट अमेरिकी अधिकारियों की भागीदारी वाली उच्च स्तरीय वार्ता से ईरान की अनुपस्थिति के बावजूद इस्लामिक गणराज्य के साथ राजनयिक प्रक्रिया के बारे में आशावाद व्यक्त किया था। नवनिर्मित थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी का दौरा करने के लिए नॉर्थ डकोटा रवाना होते समय पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि होम्सुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले

जहाजों पर हमलों के जवाब में इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ हाल ही में की गई सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा सकारात्मक रूप से आगे बढ़ी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा: अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि हालिया हमलों के बाद ईरान ने अपना रुख बदल लिया है। तेहरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर वाशिंगटन के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराते हुए, ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, ‘ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। अन्यथा, हम जिन चीजों की जांच करते हैं, जो भी कार्रवाई करते हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि देश में पहले कभी इस तरह की गतिविधि नहीं हुई है जैसी कि अभी हो रही है।’

थानों में लंबित केस, मैदान में जनचौपाल! पुलिस की प्राथमिकताओं पर जनता के तीखे सवाल



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मध्य प्रदेश में चल रहे आप की पुलिस आपके द्वार जैसे जनसंपर्क कार्यक्रमों को लेकर अब आम नागरिकों के बीच बहस तेज होती जा रही है। एक ओर पुलिस विभाग इन आयोजनों को जनता से संवाद विश्वास और कानून के प्रति जागरूकता

बढ़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं उनका मानना है कि यदि पुलिस बल का अधिक समय और संसाधन विवेचना, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी तथा अपराधियों के विरुद्ध अभियान में लगाया जाए तो आम जनता को उसका सीधा लाभ मिलेगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जनचौपाल जैसे कार्यक्रमों की व्यवस्थाएं भी अक्सर थाना स्तर पर ही कराई जाती हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि यदि इन आयोजनों के लिए अलग बजट उपलब्ध नहीं है तो व्यवस्थाओं का आर्थिक बोझ किस प्रकार वहन किया जाता है। इस विषय पर विभाग को पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की शंका की स्थिति न बने। लोगों का कहना है कि पुलिस बल पहले से ही कई स्थानों पर सीमित

संसाधनों और स्टॉफ की कमी के बीच कार्य कर रहा है। ऐसे में कानून-व्यवस्था, विवेचना, गश्त, न्यायालयीन कार्य और जनसंपर्क कार्यक्रम सभी जिम्मेदारियों का संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नागरिकों का सुझाव है कि जनसंपर्क के साथ-साथ प्रत्येक थाने में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा, फरार आरोपियों की धरपकड़ और गंभीर अपराधों के त्वरित निराकरण पर विशेष अभियान चलाया जाए। कुछ नागरिकों ने यह भी सवाल उठाया कि चर्चित मामलों में यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई हो तो अपराधियों का मनोबल स्वतः कमजोर होगा उनका कहना है कि पुलिस की कार्रवाई जितनी तेज और निर्णायक होगी अपराधियों को कानून से बच निकलने का अवसर उतना ही कम मिलेगा इसी के साथ शहर

में बढ़ते नशे को लेकर भी लोगों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। नागरिकों का कहना है कि युवाओं को नशीली दवाओं कुफ सिरप और अन्य मादक पदार्थों की गिरफ्त से बचना आज सबसे बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है उनका आरोप है कि कुछ क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की उपलब्धता को लेकर समय-समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं लोगों की मांग है कि ऐसे मामलों में छोट्टे विक्रेताओं तक सीमित रहने के बजाय पूरे सप्लाइ नेटवर्क की जांच कर मुख्य तस्करों तक कार्रवाई पहुंचनी चाहिए यदि कहीं अवैध विक्रेता की शिकायतें हैं तो उनका सत्यापन कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जनप्रतिनिधि समय-समय पर विकास सुशासन और नशामुक्त समाज की बात करते हैं ऐसे में आम

नागरिकों की अपेक्षा है कि पुलिस और प्रशासन भी अपराध नियंत्रण ,लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण नशे के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई और जनता के साथ सम्मानजनक व्यवहार को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। लोगों का मानना है कि जब थाने मजबूत होंगे अपराधियों पर समयबद्ध कार्रवाई होगी और आम नागरिक बिना भय के अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे तभी पुलिस और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता और अधिक मजबूत होगा। जनचौपाल निश्चित रूप से उपयोगी पहल हो सकती है लेकिन उसकी सफलता का वास्तविक पैमाना वही होगा जब उसका प्रभाव थानों की कार्यप्रणाली अपराध नियंत्रण और जनता को मिलने वाले न्याय में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

मऊगंज में 7 फरार आरोपियों पर इनाम घोषित, पुलिस ने की सूचना देने की अपील



मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। जिले में फरार चल रहे सात आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मऊगंज पुलिस ने इनाम घोषित किया है गुरुवार शाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक की ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि आरोपियों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित थाना या ज़िला पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी तथा नियमानुसार इनाम की राशि भी प्रदान की जाएगी।

जानकारी के अनुसार थाना लौर के अपराध क्रमांक 442/26 में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 8,

21, 22 एवं 5/13 के तहत फरार रंजना साकेत पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है इसी तरह थाना हनुमना के अपराध क्रमांक 482/26 में दर्ज मामले में तीन आरोपियों सोनू उर्फ सोहनलाल कुशवाहा (32), लालमणि कुशवाहा (37) और रामप्रसाद कुशवाहा (55) पर प्रत्येक पर 2-2 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। वहीं थाना मऊगंज के अपराध क्रमांक 250/26 में आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत दर्ज मामले में शैलेन्द्र उर्फ शैलू सिंह (40), प्रिंस उर्फ हरकिश सिंह (29) और अवधेश जैसवाल (52) फरार हैं जिन पर प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपये का इनाम रखा गया है पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है अधिकारियों ने कहा कि सूचना देने वाले नागरिकों की पहचान सुरक्षित रखी जाएगी और उन्हें नियमानुसार इनाम भी दिया जाएगा।

सिंगरौली में 25 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण मुक्त, अवैध कब्जे हटाकर होगा पौधारोपण



मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले के कथुआ वन पक्षिेत्र में वन विभाग ने गुस्वार को अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को कब्जामुक्त कराया प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में दिलीरी एवं नौगई गांवों में लंबे समय से वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटया गया। कार्रवाई के दौरान कई कच्ची झोपड़ियां और



मकानों को हटकर जमीन को वन विभाग के कब्जे में लिया गया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार दिलीरी गांव में लगभग 10 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई झोपड़ियों को हटकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं नौगई गांव में नल-जल योजना से प्रभावित भूमि के बदले वन विभाग को हस्तांतरित 15 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर भी अवैध कब्जे पाए गए थे

विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए यहां बने कच्चे मकानों और अन्य अस्थायी निर्माणों को हटवा दिया। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अचानक नहीं की गई संबंधित लोगों को पहले कई बार नोटिस जारी किए गए थे और स्वेच्छ से कब्जा हटाने के लिए समझाझष भी दी गई थी। इसके बावजूद जब अतिक्रमण नहीं हटया गया तब वन अधिनियम के

प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्रवाई की गई। यह अभियान कथुआ वन पक्षिक्षेत्र के रंजर दिव्यांशु सिंह बघेल के नेतृत्व में चलाया गया। कार्रवाई के दौरान वन विभाग, गजस्थ विभाग और पुलिस प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे प्रशासन की सतर्कता और सुस्धा व्यवस्था के चलते पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई वन विभाग ने स्पष्ट किया कि वन भूमि सार्वजनिक संपत्ति है और इस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा कानूनन अपराध है विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे वन भूमि पर अतिक्रमण न करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें।

हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल, मनगवां पुलिस की तत्परता से बची जान



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मनगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जरहा स्थित गड्स मिल के पास बुधवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पीछे से आए एक अज्ञात तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और चालक से मौके से फरार हो गया। हादसे मेंछैकोड़ी साकेत (55 वर्ष), निवासी बस्ती थाना देवतलाब, हाल

शाहपुर जिला मऊगंज तथारजलखन साकेत (31 वर्ष), निवासी शाहपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवक मोटरसाइकिल क्रमांक MP 17 E 1118 से रीवा से बस्ती की ओर जा रहे थे तभी यह दुर्घटना हुई टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिरकर बुले तरह लहलुहान हो गए और उनके सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई घटना की सूचना मिलते ही मनगवां थाना पुलिस की एफआरबी

टीम तुरंत मौके पर पहुंची घायलों की नाजुक स्थिति को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने बिना देरी किए एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना स्वयं रेस्क्यू शुरू किया आरक्षकशिखेंद्र मिश्रा, आरक्षकदेवेंद्र गोयल और एफआरबी स्टाफउमेश कुमार ने दोनों घायलों को सावधानीपूर्वक पुलिस वाहन में रखकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनगवां पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार, यदि समय पर उपचार नहीं मिलता तो अत्यधिक रक्तस्राव के कारण स्थिति गंभीर हो सकती थी पुलिस की तत्परता से दोनों की जान बच सकी फिन्हालल दोनों बायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने अज्ञात बोलेरो वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

किराना दुकान में रहस्यमयी आग, 25 लाख का नुकसान

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सीधी जिले के सेमरिया थाना अंतर्गत बहनी पुलिस चौकी क्षेत्र में स्थित 'मंजू किराना स्टोर' में संधिध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई इस घटना में लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है जिसमें शॉर्ट सर्किट और साजिश दोनों पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। दुकान संचालक भागवानदीन गुप्ता ने बताया कि वे प्रतिदिन की तरह रात में दुकान बंद करके घर चले गए थे सुबह स्थानीय लोगों ने दुकान से धुआं और आग की लपटें उठी देखी और उन्हें इसकी सूचना दी।

विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए हर माह तीन स्टरो पर होगी जनसुनवाई

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए अब प्रत्येक माह तीन स्टरो पर नियमित जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता (संचालन एवं संभारण) द्वारा यह जानकारी दी गई। मुख्य महाप्रबंधक, जबलपुर के निर्देशानुसार यह व्यवस्था वृत्त, संभाग एवं वितरण केंद्र स्तर पर लागू की गई है जिससे उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को

वितरण केंद्र स्तर, द्वितीय मंगलवार को संभागीय कार्यालय स्तर तथा तृतीय मंगलवार को वृत्त कार्यालय स्तर पर जनसुनवाई आयोजित की जाएगी इस प्रणाली से उपभोक्ताओं को अपनी समस्याएं सीधे संबंधित स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का मौके पर ही पंजीयन किया जाएगा तथा उनके निराकरण के लिए निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण कर त्वरित समाधान किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक पेेशानी का सामना न करना पड़े।

स्व-सहायता समूहों को मिलेगा बैंक ऋण, कलेक्टर ने तय किए वार्षिक लक्ष्य

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) की बैठक आयोजित की गई बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्व-सहायता समूहों के बैंक लिंकेज (सीसीएल) तथा मुद्रा ऋण के बैंकवार एवं शाखावार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए बैठक में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कुल 6060 स्व-सहायता समूहों को 133 करोड़ रुपये के बैंक लिंकेज



का लक्ष्य निर्धारित किया गया इसमें मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक को 3839 समूहों के लिए 87.18 करोड़ रुपये, ग्रुपियन बैंक ऑफ इंडिया को 1220 समूहों के लिए 27.05 करोड़ रुपये, इंडियन बैंक को 404 समूहों के लिए 6.65 करोड़ रुपये, पंजाब नेशनल बैंक को 283 समूहों के लिए 6.05 करोड़ रुपये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 197 समूहों के लिए 3.99 करोड़ रुपये तथा भारतीय

स्टेट बैंक को 117 समूहों के लिए 2.08 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है इसी प्रकार व्यक्तिगत उद्यम ऋण (मुद्रा ऋण) के अंतर्गत 1000 हितग्राहियों को 10 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया इसमें मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक को 650, ग्रुपियन बैंक ऑफ इंडिया को 211, पंजाब नेशनल बैंक को 48, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 36, भारतीय स्टेट बैंक को

31 तथा इंडियन बैंक को 24 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य सौंपा गया। कलेक्टर विकास मिश्रा ने बैठक में सभी बैंकर्स एवं मिशन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्व-सहायता समूहों के बैंक लिंकेज को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के तहत 30 सितंबर 2026 तक 70 प्रतिशत तथा 30 दिसंबर 2026 तक 100 प्रतिशत लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है तो संबंधित बैंक या मिशन टीम की जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मऊगंज में दिव्यांगजनों के हित में कलेक्टर ने ली बैठक, योजनाओं के समयबद्ध लाभ के लिए निर्देश

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन ने गुरुवार शाम कलेक्टर कक्ष में दिव्यांग प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर और प्राथमिकता से पहुंचाने के निर्देश दिए बैठक में दिव्यांगजनों की समस्याओं एवं मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि दिव्यांगजनों को सभी सुविधाएं पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराई जाएं। दिव्यांग प्रतिनिधियों ने बैठक के दौरान कई प्रमुख मांगें रखीं, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, दिव्यांग पेंशन का नियमित भुगतान, स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण, जनकल्याणकारी योजनाओं में प्राथमिकता तथा पात्र दिव्यांगों के नाम बीपीएल सूची में शामिल करना शामिल रहा कलेक्टर ने संबंधित विभागों को इन सभी आवेदनों की जांच कर पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभ देने के निर्देश दिए प्रतिनिधियों ने शासकीय दुकानों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का सुझाव भी दिया।

मिशन कर्मयोगी के तहत 'कर्मयोगी कर्तव्य' प्रशिक्षण 31 दिसंबर तक होंगे आयोजित

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। लोकसेवकों में सेवा भावना एवं लोक-केंद्रित प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत 'कर्मयोगी कर्तव्य' प्रशिक्षण कार्यक्रम 31 दिसंबर 2026 तक आयोजित किए जाएंगे इस संबंध में कलेक्टर विकास मिश्रा ने जिले के समस्त विभागों एवं कार्यालय प्रमुखों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डिजिटल लर्निंग और व्यवहारगत प्रशिक्षण कार्यशालाओं के जरिए प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे प्रशासनिक दक्षता और सेवा गुणवत्ता में सुधार हो सके प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि लगभग 4 घंटे 30 मिनट निर्धारित की गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं जिले, तहसील एवं विकासखंड स्तर पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर, अर्थात् 31 दिसंबर 2026 से पूर्व पूर्ण कर ली

जाएं। इसके साथ ही सभी प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं का आईगाई पोर्टल पर पंजीयन एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर ने सभी विभागध्यक्षों एवं कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अपने कार्यालयों में कार्यरत क्लास-1, क्लास-2, क्लास-3 एवं सविदा लोकसेवकों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार करें यह जानकारी एक्सेल शीट एवं हार्ड कॉपी दोनों रूप में संकलित कर एक सप्ताह के भीतर एनआईसी सीधी को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि समय पर डेटा उपलब्ध होने से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा और मिशन कर्मयोगी के उद्देश्यों की प्रभावी पूर्ति संभव होगी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह पहल प्रशासन को अधिक उत्तरदायी, दक्ष और जनहितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और गांवों के समग्र विकास को नई गति देने के उद्देश्य से 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' का जिला स्तरीय शुभारंभ गुरुवार को स्थानीय मानस भवन में किया गया कार्यक्रम में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, विधायक रीती पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष

मंजू सिंह, जनपद पंचायत सीधी अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह परिहार तथा जनपद पंचायत कुसमी अध्यक्ष श्यामवती सिंह सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के ग्राम मुक्तावरिपल्ली से केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मिशन के



राष्ट्रव्यापी शुभारंभ का सीधा प्रसारण देखा और सुना गया। सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि यह मिशन विकसित ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ग्रामीण विकास को नई दिशा दे रही है और अब योजनाओं की राशि

सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंचने से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था को तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी जबकि पहले यह सीमा 100 दिन थी साथ ही मजदूरी बढ़कर 300 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं

कराया जाता है तो पात्र हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। विधायक रीती पाठक ने कहा कि यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सशक्त बनाते हुए ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को पारदर्शी और विकासोन्मुख बनाएगा उन्होंने बताया कि जल संरक्षण, चेक डैम, तालाबों का पुनरुद्धार, वनीकरण, ग्रामीण सड़कें, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रामीण हाट, डेयरी अवसंरचना तथा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने वाले कार्यों को मिशन में प्राथमिकता दी जाएगी जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह तथा अन्य जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ग्राम पंचायत आधारित विकास मॉडल से स्थानीय

आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आधारभूत सुविधाओं और आजीविका के नए अवसर सृजित होंगे। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य प्रदीप शुक्ला, समाजसेवी इन्द्रशरण सिंह चौहान, पंकज पाण्डेय, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेन्द्र सिंह सोलंकी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी धनंजय मिश्रा, जनपद पंचायत सीधी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंद्रलाल पानिका, सरपंच, पंचायत प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे सभी ने मिशन के सफल क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लिया।

नौकरशाही का भ्रष्टाचार एक नासूर बन गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम दावों के बाद भी नौकरशाहों के भ्रष्टाचार पर कहीं कोई प्रभावी लगाम लगती नहीं दिखती। सीबीआई की ओर से तीन करोड़ रुपये की रिश्ततखोरी के मामले में आईपीएस अधिकारी दीपक गहलावत की गिरफ्तारी प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर फिर से ध्यान आकर्षित कर रही है। दीपक गहलावत को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया, वह नकली दवा बनाने वाले रैकेट की जांच से जुड़ा है। इस रिश्ततखोरी कांड के समय गहलावत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर	तैनात थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने तीन करोड़ रुपये की रिश्तत के बदले अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए नकली दवा बनाने के आरोपित कारोबारी को सीबीआई जांच से बचाने का भरोसा दिया। उन्होंने जांच एजेंसी के अधिकारियों पर इसके लिए दबाव भी बनाया। कहना कठिन है कि इस मामले की तह तक पहुंचने और दीपक गहलावत को उनके किए की सजा दिलाने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन यह	एक तरह से बाड़ खेत को खाए वाला एक लेकिन यह बहुत कम सुनने को मिलता है कि उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनाया गया। भ्रष्ट अधिकारियों को समय रहते दंड न दिए जाने का परिणाम यह है कि उनका भ्रष्टाचार गंभीर किस्म के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी भी होती है और उनके पास से अकूल संपत्ति भी बरामद होती है,	संपादकीय	सरकारी अस्पतालों के लिए दवाएं और मेडिकल उपकरणों की खरीद में घोटाले का है। यह घोटाला 650 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है। वास्तव में यह घोटाला नहीं एक तरह की खुली लूट थी। इसे इससे समझा जा सकता है कि बिना जरूरत कई गुना महंगे दामों पर दवाएं और मेडिकल उपकरण खरीदे गए। ऐसा लगता है कि किसी को नियम-कानूनों की कहीं कोई परवाह नहीं थी। इस मामले में स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व महानिदेशक डा. वत्सला अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। इस घोटाले में किस तरह करोड़ों के वारे-न्यारे किए जा रहे थे, यह इससे समझा जा सकता है कि 650 करोड़ रुपये में से करीब 50 प्रतिशत भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों की जेब में गए। नौकरशाही का भ्रष्टाचार एक नासूर बन गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम दावों के बाद भी नौकरशाहों के भ्रष्टाचार पर कहीं कोई प्रभावी लगाम लगती नहीं दिखती।
---	---	---	---------------------	--

संवेदना का शासन: जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने थामा कैंसर पीड़ित का हाथ

कुमार कृष्णन

राजनीति केवल नीतियां बनाने या विकास योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं होती। उसका सबसे मानवीय पक्ष तब सामने आता है जब जनप्रतिनिधि किसी जरूरतमंद की पीड़ा को अपनी संवेदना से महसूस कर तत्काल सहायता का हाथ बढ़ाता है। मुंगेर जिले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ऐसा ही एक मानवीय और संवेदनशील स्वरूप देखने को मिला, जिसने उपस्थित लोगों के मन पर गहरी छाप छोड़ दी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी टेटिया बंकर प्रखंड के देवघरा स्थित प्रसिद्ध उच्चेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर का निरीक्षण कर रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के बीच उनकी नजर भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग पर पड़ी। वह थे भंडार गांव के 65 वर्षीय राजेंद्र यादव, जो लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बीमारी और आर्थिक तंगी ने उन्हें इस स्थिति में ला खड़ा किया था कि वे अपने इलाज की उम्मीद लगभग खो चुके थे।

मुख्यमंत्री के सामने पहुंचते ही राजेंद्र यादव ने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई और इलाज के लिए सहायता की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने बिना किसी औपचारिकता के उन्हें अपने पास बुलाया, उनकी पूरी बात धैर्यपूर्वक सुनी और स्थिति की गंभीरता को समझा। इसके बाद उन्होंने मौके पर मौजूद जिला पदाधिकारी निखिल धनराज निम्पाणीकर को स्पष्ट निदेश दिया कि राजेंद्र यादव के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए तथा उन्हें निःशुल्क और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी स्तर पर इलाज में बाधा नहीं आनी चाहिए। यह निदेश केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं था, बल्कि एक ऐसे नागरिक के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक था जो बीमारी और आर्थिक कठिनाइयों के कारण जीवन से संघर्ष कर रहा है।

इस घटना ने यह संदेश भी दिया कि शासन की सफलता केवल योजनाओं के निर्माण में नहीं, बल्कि उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में है। जब कोई मुख्यमंत्री स्वयं किसी पीड़ित की व्यथा सुनकर तत्काल कार्रवाई करता है तो प्रशासनिक तंत्र भी अधिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित होता है।

राजेंद्र यादव की आंखों में उस समय आशा की नई किरण दिखाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया और कहा कि अब उन्हें विश्वास है कि उनका इलाज और आवश्यक औपरेशन बिना आर्थिक बोझ के संभव हो सकेगा। उनके चेहरे की राहत यह बता रही थी कि समय पर मिला भरोसा भी किसी औषधि से कम नहीं होता।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इस पहल की स्थानीय लोगों ने भी खुलकर सराहना की। लोगों का कहना था कि जनप्रतिनिधि तभी जनता के दिलों में स्थान बनाते हैं जब वे आम लोगों के दुख-दर्द को अपना समझकर उसके समाधान के लिए तत्परता दिखाते हैं। ऐसी घटनाएं जनता और सरकार के बीच विश्वास को और मजबूत करती हैं।

बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर एक कैंसर पीड़ित की सहायता सुनिश्चित करना इन प्रयासों को मानवीय स्पर्श प्रदान करता है।

आज के समय में, जब राजनीति पर अक्सर आरोप-प्रत्यारोप हावी रहते हैं, तब इस प्रकार की घटनाएं यह विश्वास जगाती हैं कि जनसेवा का मूल उद्देश्य अभी भी जीवित है। किसी पीड़ित व्यक्ति की आंखों में उम्मीद लौटाना और उसके जीवन को बचाने के लिए तत्परता दिखाना किसी भी जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है।

दिल्ली: वायु प्रदूषण के साथ ओजोन प्रदूषण की चुनौती

राजधानी दिल्ली वर्षों से वायु प्रदूषण की भयावह समस्या से जूझती रही है। हर सर्दी में धुंध की मोटी चादर, जहरीली हवा और दमघोंट वातावरण राष्ट्रीय चिंता का विषय बनते हैं। अब तक इस संकट की चर्चा मुख्यतः पीएम 2.5, पीएम 10, पराली और वाहनों के धुएँ तक सीमित रही, लेकिन अब एक नया और अधिक खतरनाक खतरा तेजी से उभरकर सामने आया है-भूतलीय (ग्राउंड लेवल) ओजोन प्रदूषण। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की हालिया रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, जयपुर, चंडीगढ़ और अहमदाबाद जैसे शहर भी ओजोन प्रदूषण की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। यह प्रदूषण दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके दुष्प्रभाव धीरे-धीरे मानव जीवन, कृषि और पर्यावरण को भीतर तक बीमार कर रहे हैं। विडम्बना यह है कि प्रदूषण जैसे गंभीर विषय को भी अक्सर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित कर दिया जाता है। कभी किसानों की पराली को संपूर्ण दोषी ठहरा दिया जाता है तो कभी केवल वाहनों को।

ललित गर्ग

जबकि वास्तविकता कहीं अधिक व्यापक है। यदि समस्या की जड़ तक पहुँचना है तो अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध औद्योगिकीकरण, ऊर्जा उपभोग की वर्तमान व्यवस्था और विकास के मौजूदा मॉडल पर गंभीर पुनर्विचार करना होगा। दिल्ली आज केवल देश की राजधानी नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा प्रदूषण हॉटस्पॉट भी बन चुकी है। गर्मियों में बढ़ते तापमान, तेज धूप और वाहनों एवं उद्योगों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक प्रतिक्रिया से भूतलीय ओजोन बनती है। यह वही ओजोन नहीं है जो वायुमंडल की ऊपरी परत में पृथ्वी को अतिरिक्त किरणों से बचाती है। घरातल पर बनने वाली ओजोन एक विषैली गैस है, जो फेफड़ों की कार्यक्षमता कम करती है, दमा के रोगियों की स्थिति बिगाड़ती है, आँखों में जलन पैदा करती है तथा हृदय रोगों का जोखिम बढ़ाती है। आज दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में लोग सांस लेने में कठिनाई, एलर्जी और अस्थमा जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें ओजोन प्रदूषण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने जैसे निर्णय निश्चित रूप से सकारात्मक हैं। यदि इन

योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो आने वाले वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सार्थक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन केवल वाहन नीति से समस्या का समाधान संभव नहीं है। वास्तविक संकट अनियोजित शहरीकरण का है। पिछले दो दशकों में दिल्ली और उसके लगे क्षेत्रों में जिस तेजी से खेत, तालाब और हरित क्षेत्र कंक्रीट के जंगलों में बदले हैं, उसने प्राकृतिक संतुलन को गहरा आघात पहुँचाया है। जहाँ कभी वर्षा का पानी धरती में समा जाता था, वहाँ अब सीमेंट और डामर की सतह है। पारंपरिक जलस्रोत मिट गए, पेड़ों की संख्या घटी और गर्मी बढ़ती गई। यही कारण है कि शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री अधिक रहने लगा है। यही अतिरिक्त गर्मी ओजोन बनने की प्रक्रिया को और तेज करती है। आज महानगरों का विस्तार विकास का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह विकास प्रकृति की कीमत पर हो रहा है। शहरों को सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, आवास चाहिए, उद्योग चाहिए। इन सबके लिए खेत समाप्त हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं और जलस्रोत नष्ट हो रहे हैं। परिणामस्वरूप प्रदूषण केवल हवा तक सीमित नहीं है। यह कृषि उत्पादन को भी प्रभावित करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि ओजोन फसलों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित कर उत्पादन घटा देती है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित मानसून और बढ़ती गर्मी पहले ही किसानों के सामने बड़ी चुनौती बने हुए हैं, ओजोन प्रदूषण कृषि संकट को और गहरा कर सकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक शहरों में वायु गुणवत्ता



ध्यान रखना होगा कि बिजली यदि कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से आ रही तो प्रदूषण केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होगा। इसलिए स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा और हरित परिवहन को समानांतर गति से बढ़ाना आवश्यक है। ओजोन प्रदूषण केवल मानव स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह कृषि उत्पादन को भी प्रभावित करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि ओजोन फसलों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित कर उत्पादन घटा देती है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित मानसून और बढ़ती गर्मी पहले ही किसानों के सामने बड़ी चुनौती बने हुए हैं, ओजोन प्रदूषण कृषि संकट को और गहरा कर सकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक शहरों में वायु गुणवत्ता

सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, किंतु अब समय आ गया है कि इसकी रणनीति का विस्तार किया जाए। केवल पार्टिकुलेट मैटर पर ध्यान देने के बजाय ओजोन जैसे द्वितीयक प्रदूषकों की निगरानी, वैज्ञानिक अध्ययन और नियंत्रण को भी समान बल देना होगा। वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र को अधिक व्यापक, आधुनिक और पारदर्शी बनाना होगा। समस्या के समाधान में नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कचरा जलाना, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, खुले में ईंधन जलाना, प्लास्टिक और औद्योगिक कचरे का अनुचित निस्तारण जैसी आदतों में परिवर्तन लाना होगा। अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, साइकिल और पैदल चलने की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा।

शहरों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, हरित पट्टियों का विकास और पारंपरिक जलस्रोतों का पुनर्जीवन भी प्रदूषण नियंत्रण की प्रभावी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। वायु प्रदूषण केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक संकट भी है। बढ़ती बीमारियाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ डालती हैं, कार्यक्षमता घटाती हैं और करोड़ों रुपये की आर्थिक हानि का कारण बनती हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि प्रदूषण बच्चों और युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। यदि आज निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को इसका कहीं अधिक गंभीर मूल्य चुकाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम स्वागतयोग्य हैं और उनसे सकारात्मक परिणामों की आशा की जा सकती है, किंतु यह तभी संभव होगा जब केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, उद्योग, वैज्ञानिक समुदाय और नागरिक समाज मिलकर समन्वित प्रयास करें। प्रदूषण किसी एक सरकार, एक मौसम या एक कारण की समस्या नहीं है। यह हमारे विकास मॉडल, जीवनशैली और पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण का परिणाम है। आज आवश्यकता दोषारोपण की नहीं, बल्कि दूरदर्शी नीति और सामूहिक उत्तरदायित्व की है। अन्त्या ओजोन जैसी अदृश्य गैस हमारे शहरों को धीरे-धीरे बीमार करती रहेंगी और विकास का यह मॉडल स्वयं मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा।

विभागों की मलाई पर तकरार-भ्रष्टाचार पर कैसे होगा वार ?

वैश्विक स्तरपर आज सारी दुनियाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के दंश से अर्थव्यवस्था में कमजोरी महसूस कर रही है, क्योंकि यह भ्रष्टाचार रूपी काली कमाई भ्रष्टाचारियों द्वारा बेहद सरपेंस वाली जगह पर छुपा कर रखा जाता है, जो अर्थव्यवस्था के सर्कुलेशन में काम नहीं आती । मसलन 2000 के नोटों की लंबी राशि चलन में नहीं आ रही थी यानी मतलब साफ है भ्रष्टाचार्यों के पास लॉक हो गई थी,नतीजा नोटों की नोटबंदी ही पर्याय था ।

एडवोकेट किशन सनमुखसरा भावनानी

परंतु बहुत ताजुब की बात है एक ओर जहां सरकार भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस करने कमर कसकर भिड़ी हुई है दूसरी ओर हमेशा देखा जाता है की राजनीति में सहयोगी पार्टी या पार्टी के अंदर ही पार्टी के कद्दावर नेताओं में मंत्रालय के विभागों की मलाई पर तकरार होती है, याने सरकारी टेंडर में परसेटेंज के मामले होते हैं,इसीलिए ही 40 या 50 पैसेट के आरोप प्रत्यारोप राजनीति में सभी बातें एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं अक्सर चुनवाव जीते हुए व्यक्तियों से लेकर मंत्री व चपरसी से लेकर उच्च पदासीन अधिकारी इसमें शामिल होते हैं तो फिर भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति का क्या अर्थ हुआ? जो रेखांकित करने वाली बात है, जिसका सटीक उदाहरण महाराष्ट्र के एक नेता पर गुहमंत्री होने के बावजूद 100 करोड़ प्रतिमाह का आरोप लगा था वो जेल भी गए थे। ऐसे अनेक आरोप राजनीतिज्ञों मंत्रियों पर लगाते रहते हैं जो रेखा रेखांकित करने वाली बात है, जिससे क्लियर होता है कि भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे की ओर चलता है,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध

जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगेविभागों की मलाई पर तकरार, भ्रष्टाचार पर कैसे होगा पलटवार! तथा भ्रष्ट प्लस अचार एट दरेट ऑफ भ्रष्टाचार, लोक निर्माण सरकारी टेंडर गुह परिवहन मंत्रालयों को आखिर क्यों मलाई वाला विभाग कहा जाता है? साथियों बात अगर हम भ्रष्टाचार के अर्थ को समझने की करें तो, भ्रष्टाचार शब्द दो शब्दों की संघि से बना है - भ्रष्ट +आचार, जिनके निम्न अर्थ हैं- भ्रष्ट=दूषित,गंदा, अनैतिक गलत,आपराधिक,आचार=आचरण, व्यवहार,कार्यकलाप कार्य,तो सीधे शब्दों में कहें तो भ्रष्टाचार का तात्पर्य उस कार्य से है जो गलत हो, अनैतिक हो, आपराधिक हो या दूषित हो।हमारे राजनेताओं की कुपा से आजकल यह शब्द मुख्यतया राजनैतिक संदर्भ में प्रयोग होता है लेकिन सामान्यतया हर वह आचरण भ्रष्टाचार है जो कि किसी गलत उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनैतिक ढंग से और दुर्भावना से किया जाए।केवल सरकारी कार्यों में घोटाले करना ही भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि अपने आदर्शों से समझौता करना और निजी लाभ के लिए किसी अन्य को पीड़ा पहुंचाना भी भ्रष्टाचार है।दूधवाले का

दूध में पानी मिलाना भी भ्रष्टाचार है और शिक्षक का कक्षा में ना पढ़ाना भी भ्रष्टाचार है। अधिकारी का काम ना करना भी भ्रष्टाचार है और काम के बदले रिश्तत मांगना भी भ्रष्टाचार है। टैक्स चोरी करना भी भ्रष्टाचार है और यातायात के नियमों को ना मानना भी भ्रष्टाचार है।सार्वजनिक परिवहन की घोटाले करना ही नहीं है बल्कि निजी स्वार्थ सिद्धि हेतु किया गया हर गलत आचरण ही भ्रष्टाचार है। साथियों बात अगर हम भ्रष्टाचार से आर्थिक दुष्प्रभाव की करें तो,भ्रष्टाचार का आर्थिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है. मसलन, भ्रष्टाचार के चलते सड़क कमजोर बनायी जाती है, जिससे वह जल्दी टूट जाती है, इस फॉर्मूले के अनुसार भारत और चीन की विकास दर कम होनी चाहिए थी, क्योंकि ये देश ज्यादा भ्रष्ट है,परंतु वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है।भारत और चीन की विकास दर अधिक है।भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि भ्रष्टाचार से प्राप्त रकम का उपयोग किस प्रकार किया जाता है।हामान लीजिए एक करोड़ रुपये के सड़क बनाने के ठेके में से 50 लाख रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, सड़क घटिया बनी. प्रश्न

उठता है कि घूस की 50 लाख की रकम का उपयोग किस प्रकार हुआ यदि इस रकम को शेयर बाजार में लगाया गया तो भ्रष्टाचार का आर्थिक विकास पर दुष्प्रभाव कुछ घटता है,दक्षिणी अमेरिकी देशों एवं भारत में यह अंतर साफ है। दक्षिण अमेरिका के नेताओं ने घूस की रकम को स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा करा दिया। नतीजा विकास में गिरावट आयी,परंतु भारतीय नेताओं ने स्विस बैंकों में जमा कराने के साथ- साथ घरेलू उद्यमियों के पास भी रकम जमा करायी। यदि घूस की रकम का निवेश किया जाये, तो अनैतिक भ्रष्टाचार का आर्थिक सुप्रभाव भी पड़ सकता है।हामान लीजिए सरकारी निवेश में औसतन 70 फीसदी रकम का सदुपयोग होता है, जबकि निजी निवेश में 90 फीसदी का, ऐसे में यदि एक करोड़ रुपये को भ्रष्टाचार के माध्यम से निकाल कर निजी कंपनियों में लगा दिया जाये, तो 20 लाख रुपये के नाम से जानी जाती है। अपना अतिरिक्त आय में से व्यक्ति कितनी बचत करता है उसे 'बचत की प्रवृत्ति' कहा जाता है। गरीब की 100 रुपये की अतिरिक्त आय हो, तो वह 90 रुपये की खपत करता है और 10

रुपये की बचत. तुलना में अमीर को 100 रुपये की अतिरिक्त आय हो, तो वह 10 रुपये की खपत करता है और 90 रुपये की बचत करता है.मान लीजिए अमीर इंजीनियर ने गरीब किसान से 100 रुपये की घूस ली। गरीब की आय में 100 रुपये की गिरावट आयी, जिसके कारण बचत में 10 रुपये की कटौती हुई. परंतु अमीर इंजीनियर ने 100 रुपये की घूस में 90 रुपये की बचत की. इस प्रकार घूस के लेनदेन से कुल बचत में 80 रुपये की वृद्धि हुई। अमीर द्वारा गरीब का शोषण सामाजिक दृष्टि से गलत होते हुए भी आर्थिक दृष्टि से लाभकारी हो गया।भ्रष्टाचार का आर्थिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है। मसलन, भ्रष्टाचार के चलते सड़क कमजोर बनायी जाती है, जिससे वह जल्दी टूट जाती है। इस फॉर्मूले के अनुसार भारत और चीन की विकास दर कम होनी चाहिए थी, क्योंकि ये देश ज्यादा भ्रष्ट हैं। परंतु वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। भारत और चीन की विकास दर अधिक है. भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि भ्रष्टाचार से प्राप्त रकम का उपयोग किस प्रकार किया जाता है.मान लीजिए एक करोड़ रुपये के सड़क बनाने के ठेके में से 50 लाख

रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया. सड़क घटिया बनी. प्रश्न उठता है कि घूस की 50 लाख की रकम का उपयोग किस प्रकार हुआ। साथियों बात अगर हम भ्रष्टाचार के कारणों को समझने की करें तो, हम सभी ने कहीं ना कहीं इसे सिस्टम का हिस्सा मान कर अपना लिया है।हम भ्रष्टाचारियों को कोसते है पर वही अपना काम जल्दी कराने के लिये हम खुद उसे बढ़ावा भी देते हैं।।इंडिविंग लाइसेंस जल्दी नहीं बना रहा, थोड़ा खिला देंगे।पासपोर्ट के लिये पुलिस वेरिफिकेशन में समय लगेगा चलो थोड़ा साहब को खर्चा पानी दे देंगे 7हेलपेट नहीं पहना है , गाड़ी के कागज नहीं है , ट्रैफिक पुलिस वाले की 100-50 दे कर बच जायेगे 7 सरकारी टेंडर हमें ही मिले इसके लिये सरकारी बाबू को थोड़ा मिठाई भिजवा देते है।और फिर जो पैसा उनकी खातिरदारी में खर्च होगा वो हम काम की गुडवत्ता कम करके खानापूर्ति कर लेंगे 7हमारा इस सब को ले कर casual attitude (सब ठीक है) ही इस सब का जिम्मेदार है, सिर्फ सरकारों को कोसने से कुछ नहीं होगा पहला बदलाव हमें खुद से शुरू करना होगा, अपनी सोच में परिवर्तन करके।

भरतपुर में ‘विकसित भारत - RAM Act, 2025’ का राष्ट्रीय शुभारंभ, ग्रामीण विकास को मिलेगी नई दिशा



मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में गुरुवार को जनपद पंचायत भरतपुर के सभागार में ‘विकसित भारत – G RAM G Act, 2025 ‘ के राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित

इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन जनभागीदारी और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह रही जबकि अध्यक्षता जनपद पंचायत अध्यक्ष मायाप्रताप सिंह ने की इस अवसर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय सिंह



इसके लिए ग्रामीण विकास योजनाओं का पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस दौरान रोजगार सृजन, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन, ग्रामीण अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी संचालन जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई वक्ताओं ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार जब देश के गांव आर्थिक, सामाजिक और आधारभूत सुविधाओं के स्तर पर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे

बेहतर समन्वय एवं सक्रिय भागीदारी जरूरी है मुख्य अतिथि यशवंती सिंह ने कहा कि गांवों का समग्र विकास ही विकसित भारत की मजबूत नींव है उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने का आह्वान किया कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मायाप्रताप सिंह ने कहा कि जनभागीदारी से ही ग्रामीण विकास को

नई गति मिलेगी उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से शासन की योजनाओं की प्रभावी ढंग से लागू करने और ग्रामीणों को उनका अधिकतम लाभ दिलाने की अपील की। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने तथा ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का सामूहिक संकल्प लिया अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी और आत्मनिर्भर एवं समृद्ध गांवों के निर्माण का लक्ष्य तेजी से साकार होगा।



डायल-112 की तत्परता से परिवार से मिला तीन वर्षीय मासूम, देवास पुलिस की संवेदनशीलता बनी मिसाल

मीडिया ऑडीटर, देवास (निप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस की डायल-112 सेवा ने एक बार फिर अपनी तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए घर से भटक गए तीन वर्षीय मासूम को सुरक्षित उसके परिजनों से मिलाकर परिवार की खुशियां लौटा दीं यह घटना देवास जिले के औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत अमृत स्वीट्स के पास की है जहां डायल-112 के जवानों की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया जानकारी के अनुसार 1 जुलाई को राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112 भोपाल को सूचना मिली कि औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत अमृत स्वीट्स के पास करीब तीन वर्ष का एक बालक अकेला घूम रहा है बालक अपने घर का रास्ता भटक गया था और अपनी कम उम्र के कारण अपने माता-पिता या घर का पता भी नहीं बता पा रहा था। सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम ने तत्काल थाना औद्योगिक क्षेत्र में तैनात डायल-112 एफआरवी वाहन को मौके के लिए रवाना किया। कुछ ही समय में डायल-112 टीम

मौके पर पहुंच गई आरक्षक सचिन चौहान और वाहन चालक (पायलट) देवेन्द्र भारती ने बालक को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया और उसे शांत कराकर उसके परिजनों की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने मासूम को एफआरवी वाहन में बैठाकर आसपास के इलाकों में पूछताछ की और संभावित स्थानों पर उसके परिवार की खोज की लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से बालक को थाना औद्योगिक क्षेत्र लाया गया जहां उसकी देखभाल की गई। कुछ समय बाद अपने लापता बेटे की तलाश में परेशान माता-पिता थाने पहुंचे पुलिस ने आवश्यक पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मासूम को सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया अपने बच्चे को सकुशल देखकर माता-पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े उन्होंने डायल-112 सेवा और पुलिस जवानों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर पुलिस की मदद नहीं मिलती तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी।

‘सेफ क्लिक 2.0’ अभियान के तहत प्रदेशभर के स्कूलों में दिलाई गई साइबर सुरक्षा की शपथ



मीडिया ऑडीटर, भोपाल (निप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस और स्कूल शिक्षा विभाग की संयुक्त पहल ‘सेफ क्लिक 2.0 ‘अभियान के तहत बुधवार को प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों में साइबर सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए प्रार्थना सभाओं में लाखों विद्यार्थियों, शिक्षकों और

शैक्षणिक स्टाफ ने साइबर शपथ लेकर सुरक्षित एवं जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने का संकल्प लिया अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करना और डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित उपयोग के लिए प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवकी मंशा तथा पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणाके निर्देशन में संचालित इस राज्यव्यापी अभियान का आयोजन मध्यप्रदेश पुलिस के राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय एवं स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से किया गया राजधानी भोपाल से लेकर प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक एक साथ आयोजित कार्यक्रमों में साइबर सुरक्षा का संदेश विद्यार्थियों तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि आज के डिजिटल दौर में इंटरनेट, सोशल

मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म जीवन का हिस्सा बन चुके हैं लेकिन इनके साथ साइबर ठगी, फर्जी लिंक, ऑनलाइन उत्पीड़न, फेक न्यूज और डेटा चोरी जैसे खतरों भी तेजी से बढ़ रहे हैं ऐसे में प्रत्येक ऑनलाइन गतिविधि के दौरान सतर्कता और जिम्मेदारी बेहद जरूरी है साइबर शपथ के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों ने यह संकल्प लिया कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड, ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी या अन्य गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करेंगे इसके अलावा सोशल मीडिया पर अजनबियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करेंगे, अपुष्ट या भामक सूचनाएं साझा नहीं करेंगे तथा ऑनलाइन गेमिंग या चैटिंग के दौरान किसी भी प्रकार के लालच, धमकी या धोखाधड़ी का शिकार होने से बचेंगे।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 बनी आमजन का सहारा, एक सप्ताह में बना आयुष्मान कार्ड



मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन के संकल्प को साकार करने में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों के लिए प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही है इसका ताजा उदाहरण मन्नेद्राढ़ निवासी अभिनव द्विवेदी हैं जिनकी लंबे समय से लंबित आयुष्मान कार्ड की समस्या हेल्पलाइन पर शिकयत दर्ज होने के महज एक सप्ताह के भीतर हल हो गई अब उन्हें आयुष्मान भारत योजना के

तहत 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार का लाभ मिल सकेगा। जानकारी के अनुसार अभिनव द्विवेदी ने आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली थी लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी उनका कार्ड जारी नहीं हो पाया। इसके कारण वे शासन की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा से वंचित थे और इलाज संबंधी संपातित आर्थिक जिंताओं का सामना कर रहे थे कई प्रयासों के बाद भी समाधान नहीं

शिकयत के निश्चरण के बाद मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जब अभिनव से फीडबैक लिया गया तो उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी समस्या का पूरी तरह समाधान हो गया है उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की तत्पता की सरगना करते हुए कहा कि उन्हें इतनी जल्दी कार्डवाई होने की उम्मीद नहीं थी अभिनव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन वास्तव में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसेमंद माध्यम बन चुकी है जिला प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 केवल शिकयत दर्ज करने का मंच नहीं बल्कि पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध समाधान की प्रभावी व्यवस्था है।

मध्यप्रदेश पुलिस में eHRMS ई-लीव प्रणाली लागू, अब ऑनलाइन होंगे अवकाश आवेदन और स्वीकृति

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (निप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस ने पुलिस कर्मियों की सेवा प्रबंधन व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठते हुए (इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) का ई-लीव मॉड्यूल प्रदेशभर में लागू कर दिया है पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2026 से यह व्यवस्था सभी पुलिस इकाइयों में प्रभावी हो गई है इसके बाद अब प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी ऑनलाइन अवकाश आवेदन, स्वीकृति और उसकी स्थिति की जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्राप्त कर सकेंगे। नई व्यवस्था के लागू होने से पारंपरिक मैनुअल प्रक्रिया की जगह पूरी तरह डिजिटल प्रणाली ने ले ली है इससे अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और सुगम होगी, वहीं कर्मचारियों को आवेदन की वर्तमान स्थिति जानने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे पुलिस विभाग ने जुलाई 2025 से सेवा अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत की



थी इस दौरान पुलिस कर्मियों की सेवा पुस्तिकाओं की स्कैनिंग और आवश्यक सेवा संबंधी जानकारी को डिजिटल रूप में सुरक्षित किया गया मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से एक लाख से अधिक सेवा पुस्तिकाओं का डिजिटलीकरण किया गया है तथा वर्तमान में करीब एक लाख पुलिस अधिकारी और कर्मचारी प्लेटफॉर्म से जुड़े चुके हैं। विभाग ने इससे पहले 23 मार्च 2026 से ऑर्डर बुक मॉड्यूल भी शुरू किया था, जिसके माध्यम से सेवा पुस्तिका से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आदेश अब डिजिटल

रूप में सुरक्षित उपलब्ध रहेंगे इससे अभिलेखों के संरक्षण और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से प्राप्त करने में सुविधा होगी। ई-लीव मॉड्यूल को लागू करने से पहले इसे एससीआरबी, कार्मिक शाखा, विशेष शाखा, पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल और 25वीं वाहिनी भोपाल में प्रायोगिक तौर पर संचालित किया गया प्राप्त सुझावों और अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुधार किए गए जिसके बाद इसे प्रदेश की लगभग 120 पुलिस इकाइयों में लागू कर दिया गया नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी ehrms.mp.gov.in पोर्टल या eHRMS मोबाइल एप के माध्यम से अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे यह एप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आवेदन के बाद संबंधित लीव क्लर्क उसे सक्षम अधिकारी को ऑनलाइन अप्रैपत करेगा और अधिकारी भी डिजिटल माध्यम से ही अनुमति एवं स्वीकृति देंगे। कर्मचारी अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से आवेदन की अद्यतन स्थिति कभी भी देख सकेंगे।

एसडीएम जेपी गुसा पर एफआईआर का विरोध, प्रशासनिक सेवा संघ ने निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। पोहरी एसडीएम जेपी गुसा के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में दर्ज एफआईआर के विरोध में मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की शिवपुरी जिला इकाई ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर अर्पित वर्मा को ज्ञापन सौंपकर मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की है। संघ का कहना है कि एसडीएम जेपी गुसा ने 12 जून को पोहरी में पदभार ग्रहण किया था जबकि एफआईआर में उल्लेखित रिकॉर्ड दुस्स्ती का मामला 15 जून को पहली बार उनके समक्ष आया था संघ के अनुसार इस प्रकरण में आवेदक बाबू सिंह राजपूत को 6 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था और तब तक कोई अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ था। ज्ञापन में यह भी दावा किया गया है

कि शिकायतकर्ता गोविंद शिवहरे का संबंधित प्रकरण से कोई प्रत्यक्ष या कानूनी संबंध नहीं है ऐसे में उसकी शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर की निष्पक्ष जांच आवश्यक है राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने आरोप लगाया कि एसडीएम जेपी गुसा शासकीय तथा अनुसूचित जाति-जनजाति की भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं इसी से प्रभावित कुछ गुसा ने 12 जून को पोहरी में पदभार ग्रहण किया था जबकि एफआईआर में उल्लेखित रिकॉर्ड दुस्स्ती का मामला 15 जून को पहली बार उनके समक्ष आया था संघ के अनुसार इस प्रकरण में आवेदक बाबू सिंह राजपूत को 6 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था और तब तक कोई अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ था। ज्ञापन में यह भी दावा किया गया है



मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन को नई दिशा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को नए स्वरूप ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन

(ग्रामीण) – VB-G RAM G Act, 2025 ‘के रूप में लागू कर दिया है मिशन का देशव्यापी शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानने आंध्र प्रदेश के तिरुपति से वचुअल माध्यम से किया इस अवसर पर मनेन्द्राढ़-चिरमिरी-

संसाधनों का संरक्षण तथा स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण परिवारों की आजीविका को स्थायी रूप से सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2026से देशभर में लागू इस मिशन के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार का गारंटीमिलेगी। साथ ही न्यूनतम दैनिक मजदूरी 300 रुपयेनिर्धारित की गई है जबकि राष्ट्रीय औसत मजदूरी लगभग 327.40 रुपयेप्रतिदिनहोगी।मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में किया

जाएगा जिससे पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित होगा कार्यक्रम में अधिकारियों ने मिशन की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी देते हुए बताया कि जल संरक्षण, भू-जल संवर्धन, वृक्षारोपण, कृषि आधारित अधोसंरचना, तालाब निर्माण, खेत सुधार, ग्रामीण सड़क निर्माण तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुदृढ़ करने वाले कार्य भी मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे इस अवसर पर ‘एक पेड़ साँ के नाम ‘अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजेश नाहू, जिला पंचायत सदस्य उदित सारायण,

विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच, जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और अधिकधिक पौधारोपण एवं उनके संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पिपरिया सहित डोंगौर, भालौर, शंकरगढ़, कर्वाँतिया, सिरौली, चैनपुर, सलही, बेलबहरा, डोमनापारा, कोठारी, चौघडू, बौरीछाड़ एवं लालपुर ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे जन सम्मेलन के माध्यम से मिशन की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई गई और इसे गांवों के समग्र एवं टिकाऊ पंचायत उपाध्यक्ष राजेश नाहू, जिला पंचायत सदस्य उदित सारायण,

डाकखाना चौराहे पर डंपर और कार की आमने-सामने टक्कर

छतरपुर में हादसे के बाद सड़क पर लगा जाम, पन्ना जा रहा था कार सवार



मीडिया ऑडीटर,छतरपुर (निप्र)। छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के डाकखाना चौराहे पर गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे डंपर और कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि, कार चालक सुरक्षित बच गया। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त कार का पंजीयन क्रमांक MP 16 ZB 0640 है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक यह कार अधिकता राजेश सिंह बघेल की है। गुरुवार सुबह उनका चालक कार लेकर पन्ना की ओर जा रहा था। इसी दौरान डाकखाना चौराहे के पास सामने से आ रहे डंपर से उसकी टक्कर हो गई। हादसे के समय कार में चालक के अलावा कोई अन्य सवार नहीं था।

टक्कर के बाद दूसरी दिशा में जाकर रुकी कार: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद कार सड़क पर धूमकर विपरीत दिशा में जाकर रुकी। इससे पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि कार गलत दिशा में खड़ी है। मौके पर मौजूद परिजनों ने बताया कि कार गलत साइड पर नहीं चल रही थी। डंपर की टक्कर के कारण उसका रुख बदल गया था। हालांकि, हादसा किस वाहन चालक की लापरवाही से हुआ, इसका पता पुलिस जांच और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर चलेगा।

कुछ देर तक यातायात रहा प्रभावित: हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार सड़क के बीच में खड़ी रही, जिससे कुछ समय तक यातायात प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के काफी देर बाद तक मौके पर ट्रैफिक पुलिस या अन्य पुलिसकर्मी नहीं पहुंचे। इससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी हुई। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हादसे के समय किस वाहन चालक की लापरवाही थी।

मंदसौर में मजदूर ने घर में फांसी लगाकर दी जान,परिजनों से विवाद की चर्चा पुलिस परिजनों से करेगी पूछताछ

मीडिया ऑडीटर,मंदसौर (निप्र)।मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र के ग्राम लदुना में गुरुवार को एक व्यक्ति ने अपने घर में फांसी ल ग ा क र आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर सीतामऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामऊ शासकीय अस्पताल भेजा। यह घटना तब सामने आई जब परिजनों ने व्यक्ति का शव कमरे में रस्सी के फंदे से लटका हुआ देखा। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान लदुना निवासी लक्ष्मीनारायण पिता रामनारायण तेली के रूप में हुई है। बताया गया है कि वह खेती और मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्रारंभिक जानकारी में आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। हालांकि, विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार घटना से पहले मृतक का परिजनों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने इस संबंध में किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सीतामऊ थाना पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आत्महत्या के कारणों की गहन जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

सीहोर में मानसून एक्टिव, इछावर में सबसे ज्यादा बारिश

कीचड़ में फंसे वाहन और सड़क पर गिरा पेड़, वाहन फंसने से लगा जाम

● आगे भी बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार, जिले में अगले कुछ दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मानसून की सक्रियता के कारण कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने बताया कि सड़कों की मरम्मत का कार्य समय-समय पर किया जाता है।

बारिश के बाद जिले के कई इलाकों में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। चंदेरी गांव, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और बोरदी क्षेत्र में कीचड़ और पेड़ गिरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चंदेरी गांव के मुख्य मार्ग पर सड़क पर जमा मिट्टी बारिश के पानी से मिलकर दलदल में बदल गई। इस कीचड़ में एक भारी ट्रक फंस गया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात घंटों बाधित रहा।

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी कच्ची सड़कों पर जलभराव के कारण भारी कीचड़ जमा हो गया। कॉलोनी के मुख्य रास्ते पर एक वाहन कीचड़ में फंस गया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ और स्थानीय लोगों को दिक्कत हुई। बोरदी क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर एक बड़ा पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया। इस घटना में कोई वाहन चपेट में नहीं आया, लेकिन सड़क का संपर्क बाधित हो गया और दोनों ओर वाहनों की आवाजाही रुक गई।

खटिया पर सो रहे 28 साल के युवक की हत्या

खंडवा के कुसुम्बिया में सिर पर भारी वस्तु से वार, प्रेम-प्रसंग और लेन-देन का शक

मीडिया ऑडीटर, खंडवा (निप्र)। खंडवा जिले के पंधाना थाना क्षेत्र स्थित कुसुम्बिया गांव में मंगलवार रात एक 28 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। मृतक का शव बुधवार सुबह घर के आंगन में खटिया पर लहलुहान हालत में मिला। हमलावर ने उसके सिर पर किसी भारी वस्तु से वार कर इस वारदात को अंजाम दिया है। मृतक की पहचान केदार (28) पिता कुर्बान के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, केदार शादीशुदा था और मंगलवार रात भोजन करने के बाद घर के आंगन में खटिया पर सो गया था। बुधवार सुबह जब परिवार के लोगों ने उसे देखा, तो उसकी मौत हो चुकी थी और सिर पर गहरी चोट के निशान थे।

एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य, पत्नी से हुई पूछताछ: घटना की सूचना मिलते ही पंधाना पुलिस

और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने

प्रेम-प्रसंग और लेन-देन के एंगल पर पड़ताल: डीएसपी (मुख्यालय) अनिल सिंह चौहान ने बताया कि मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। शुरूआती जांच में पैसें के लेन-देन और प्रेम-प्रसंग, ये दो एंगल सामने आए हैं। पुलिस इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखकर गहराई से पड़ताल कर रही है और कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी हाथ लगे हैं।

संदिग्धों से पूछताछ जारी, जल्द होगा खुलासा: पुलिस आसपास के लोगों से लगातार जानकारी जुटा रही है। इसके अलावा संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है और कुछ लोगों से पूछताछ जारी है। डीएसपी चौहान के मुताबिक, जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

किराना व्यापारी को कार ने मारी टक्कर, गंभीर घायल

पन्ना में आरोपी ड्राइवर फरार, सड़क पार करते समय हादसा

मीडिया ऑडीटर,पन्ना (निप्र)। पन्ना शहर की इटपूरी कॉलोनी के पास गुरुवार दोपहर एक सड़क हादसा हुआ। तेज रफतार अज्ञात कार ने सड़क पार कर रहे एक किराना व्यापारी को टक्कर मार दी। हादसे में व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना दोपहर करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। इटपूरी कॉलोनी, गीता देवेंद्र कुशवाहा अपनी दुकान के पास सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान अजयगढ़ की ओर से आ रही एक तेज रफतार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे के बाद मौके पर लगी भीड़, ड्राइवर फरार टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर इन्हें सुरक्षित रखना हमारी सांस्कृतिक धरोहर और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी है। 19 मार्च से 30 जून तक चले जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान परिषद की ग्राम विकास प्रस्पुटन समितियों, नवांकुर संस्थाओं, परामर्शदाताओं एवं

सागर में तीन युवकों पर कटर से हमला, घायल

शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे, पुलिस ने दो संदिग्धों को पकड़ा

मीडिया ऑडीटर,सागर (निप्र)। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में रविशंकर स्कूल के पास बदमाशों ने तीन युवकों पर कटर से हमला कर दिया। कटर लगने से तीनों युवक गंभीर घायल हुए हैं। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरास्त में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार, कनेरा गौड़ निवासी नीरज, अजय

और पप्पू कुशवाहा बुधवार रात शादी समारोह में शामिल होने के लिए सागर आए थे। वे मोतीनगर क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल होकर बाइक से देर रात घर लौट रहे थे। इसी दौरान रविशंकर स्कूल के पास दुकान पर खड़े हुए। तभी कुछ बदमाश मौके पर आ गए। उन्होंने बाइक की चाबी और रुपयों की मांग की। पैसे नहीं देने पर मारपीट शुरू कर दी।

कटर लगने से तीनों युवक घायल: मारपीट के दौरान आरोपियों ने कटर

निकाला और नीरज, अजय और पप्पू पर हमला कर दिया। कटर लगने से तीनों युवक गंभीर घायल हुए हैं। घटना देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को बीएमसी में भर्ती कराया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। घायलों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। दो संदिग्धों को हिरास्त में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।

नर्मदापुरम में व्यापारी ने युवती से किया रेप

इंस्टाग्राम पर फ्रेंडशिप के बाद शादी का किया वादा, दो साल किया दैहिक शोषण

मीडिया ऑडीटर,नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम शहर के एक बेल्ट-चश्मा दुकानदार पर 33 साल की एक युवती ने शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया। युवती ने महिला थाने में आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया है। बुधवार को पुलिस ने आरोपी जितेंद्र राठौर निवासी रिवर व्यू कॉलोनी के पास को गिरफ्तार किया। जिसे

कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस के मुताबिक 33 साल की युवती जो शहर के एक कॉलोनी की रहने वाली है। आरोपी जितेंद्र राठौर की बाजार में चश्मे-बेल्ट की दुकान है। महिला थाना प्रभारी राखी मौर्व ने बताया आरोपी जितेंद्र शादीशुदा है। जिसका तलाक़ का केस

चल रहा है। युवती और आरोपी की तीन साल पहले 2024 में इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। कुछ समय बाद उनके बीच मोबाइल पर बातचीत होने लगी। दोस्ती प्रेम में बदल गई। फिर युवक जितेंद्र ने युवती को शादी करने का झांसा दिया। आरोपी ने अपने घर बुलाकर युवती से गलत संबंध बनाए। फिर उनके बीच कई बार संबंध बने। अप्रैल 2026 में भी आरोपी ने घर बुलाकर रेप किया। जब युवती ने शादी का बोला तो उसने कहा कि अभी तलाक़ का निर्णय हो जाने तो तब वो शादी करेगा। ऐसा कहकर युवक समय बीता था था। फिर उसने महिला थाने पहुंचकर शिकायत की। युवती की शिकायत पर आरोपी जितेंद्र राठौर के खिलाफ केस दर्ज किया। उसे गिरफ्तार कर लिया है। जिसे जेल भेजा गया।

जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन, वेदनखेड़ी में हर्षोल्लास से मनाया गया बावड़ी उत्सव

मीडिया ऑडीटर,विदिशा (निप्र)। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के विकासखंड गंजबासौदा द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर वेदनखेड़ी स्थित नृसिंह मंदिर की ऐतिहासिक बावड़ी पर भव्य 'बावड़ी उत्सव' आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों एवं वरिष्ठजनों की उपस्थिति में बावड़ी पूजन, दीप प्रज्वलन एवं आरती के साथ हुआ। आयोजन के माध्यम से जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए अतिथियों ने कहा कि 'जल संरक्षण ही भविष्य की सुरक्षा है।' उन्होंने बताया कि विकासखंड स्तर पर जल संरक्षण संबंधी गतिविधियां तीन चरणों में

संचालित की गई। उन्होंने प्राचीन जल संरचनाओं के संरक्षण एवं संवर्धन पर बल देते हुए कहा कि इन्हें सुरक्षित रखना हमारी सांस्कृतिक धरोहर और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी है। 19 मार्च से 30 जून तक चले जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान परिषद की ग्राम विकास प्रस्पुटन समितियों, नवांकुर संस्थाओं, परामर्शदाताओं एवं

विद्यार्थियों द्वारा जल संरक्षण के लिए गतिविधियां संचालित की गईं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम अनुभा जैन, नगरपालिका अध्यक्ष शशि यादव, देवेन्द्र यादव, नगरपालिका उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ), जन

अभियान परिषद की जिला समन्वयक पूजा वास्तव, ब्लॉक समन्वयक ममता राठौर सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान समय में जल संरक्षण सबसे बड़ी आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति को जल की प्रत्येक बूंद के संरक्षण के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अतिथियों ने कहा कि यह केवल 'बावड़ी उत्सव' नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने का जन-जागरण अभियान है। इस अवसर पर सभी उपस्थितजनों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान बावड़ी परिसर की विशेष स्वच्छता एवं आकर्षक सजावट की गई।

रंगोली, दीपों एवं फूल-मालाओं से बावड़ी को सजाया गया। विशाल वैरागी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत बावड़ी पूजन कराया, जिसके पश्चात जल संरक्षण विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। समापन अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सामूहिक संकल्प लिया। इस अवसर पर नवांकुर संस्था के देवेन्द्र कुमार साहू, अमित शर्मा, हजारीलाल पाटकर, धन सिंह कुशवाहा, रामचरन कुशवाहा, राजेन्द्र रघुवंशी, अभिषेक शर्मा, परामर्शदाता जगदीश प्रसाद साहू, सीमा शर्मा, रीतू दांगी, ग्राम विकास प्रस्पुटन समिति के सदस्य, सीएमसीएलडीपी के छात्र-छात्राएं एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

ग्रैंड चेस टूर क्रोएशिया: पहले दिन आर. प्रग्नानानंदा का शानदार प्रदर्शन, छठे स्थान पर रहे गुकेश

जाग्रोब एजेंसी। ग्रैंड चेस टूर 2026 के तीसरे इवेंट सुपर रैपिड और ब्लिट्ज क्रोएशिया में भारतीय खिलाड़ियों की शुरुआत अलग-अलग रही। युवा ग्रैंडमास्टर आर. प्रग्नानानंद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले दिन संयुक्त दूसरे स्थान पर जगह बनाई, जबकि मौजूदा विश्व चैंपियन डी. गुकेश छठे स्थान पर रहे। प्रग्नानानंद ने पहले मुकाबले में जर्मनी के विसेंट कीमर को हराकर शानदार शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने फ्रांस के मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव के खिलाफ ड्रॉ खेला। वहीं, दिन के तीसरे और आखिरी राउंड में उनका मुकाबला गुकेश से हुआ, जो ड्रॉ पर खत्म हुआ। पहले दिन के बाद प्रग्नानानंद के 6 में से 4 अंक हैं और वह संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। दूसरी ओर, गुकेश का पहला मैच अच्छा नहीं रहा। उन्हें मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, उन्होंने दूसरे राउंड में इवान सारिक को हराकर शानदार वापसी की। तीसरे राउंड में प्रग्नानानंद के खिलाफ उनका मुकाबला ड्रॉ रहा। तीन राउंड के बाद गुकेश के 6 में से 3 अंक हैं और वह छठे स्थान पर हैं।



रैपिड सेक्शन के अभी छह राउंड और खेले जाने बाकी हैं। पहले दिन के बाद फ्रांस के अल्लोरिजा फिरोजा 5

अंकों के साथ अकेले शीर्ष पर हैं। उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए बढ़त बनाई। खास बात यह है कि कुछ सप्ताह पहले टखने की चोट के कारण

उन्हें रोमानिया में ग्रैंड चेस टूर का एक इवेंट बीच में छोड़ना पड़ा था। अब उन्होंने शानदार वापसी करते हुए लीड हासिल कर ली है। तीसरे राउंड में उनका मुकाबला अनीश गिरी से ड्रॉ रहा, जिससे उनकी बढ़त बरकरार रही। अन्य मुकाबलों में विसेंट कीमर ने नोडिबेक अब्दुसतोरोव को हराकर जीत दर्ज की। वहीं, बोगदान-डैनियल डेक ने इवान सारिक को हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल की। मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव और जॉर्डन वैन फोर्स्ट के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा।

इस टूर्नामेंट में दो प्रारूप खेले जा रहे हैं। पहले 9 राउंड का सुपर रैपिड टूर्नामेंट होगा, जिसमें हर खिलाड़ी को 25 मिनट का समय और हर चाल पर 10 सेकंड का अतिरिक्त समय मिलेगा। इसके बाद 18 राउंड का ब्लिट्ज टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसमें हर खिलाड़ी को 5 मिनट और हर चाल पर 2 सेकंड का अतिरिक्त समय मिलेगा। रैपिड में जीत पर 2 अंक और ड्रॉ पर 1 अंक मिलता है, जबकि ब्लिट्ज में जीत पर 1 अंक और ड्रॉ पर आधा अंक दिया जाता है।

भारत की अंडर-19 और अंडर-23 टीमों घोषित विश्वनाथ और चंद्रिका अगुवाई करेंगे



नई दिल्ली एजेंसी। भारत अंडर-19 और अंडर-23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले और उभरते हुए खिलाड़ियों का मिला-जुला दल उत्तरांग। यह प्रतियोगिता 3 से 16 जुलाई के बीच इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित होगी। मौजूदा एशियन चैंपियन विश्वनाथ सुरेश और वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप गोल्ड मेडलिस्ट चंद्रिका पुजारी इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारत की अगुवाई करेंगे। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआई) ने

बुधवार को दोनों आयु वर्गों के लिए टीमों की घोषणा कर दी।

पुरुषों के अंडर-23 वर्ग में 50 किग्रा कैटेगरी में मौजूदा एशियन चैंपियन विश्वनाथ टीम की अगुवाई करेंगे, जिसमें गंगा (55 किग्रा), सागर जाखड़ (60 किग्रा), वंशज (65 किग्रा), हितेश (70 किग्रा), नीरज (75 किग्रा), आर्यन मलिक (80 किग्रा), रंजी चौधरी (85 किग्रा), हेमंत सांगवान (90 किग्रा) और ईशान कटारिया (90+ किग्रा) भी शामिल हैं। महिलाओं की अंडर-23 टीम में निधि (48 किग्रा), तनु (51 किग्रा), निशा

(54 किग्रा), प्राची (57 किग्रा), निकिता चंद (60 किग्रा), काजल (65 किग्रा), शिवानी (70 किग्रा), मुस्कान (75 किग्रा), नैना (80 किग्रा) और प्रियंका (80+ किग्रा) शामिल हैं। अंडर-19 प्रतियोगिता में, फ्यूचर्स कप गोल्ड मेडलिस्ट चंद्रिका पुजारी 51 किग्रा कैटेगरी में लड़कियों की टीम की अगुवाई करेंगी।

उनके साथ गुंजन (48 किग्रा), चिरोम जॉयश्री देवी (54 किग्रा), प्राची (57 किग्रा), चाहत (60 किग्रा), वंशिका (65 किग्रा), लक्ष्म (70 किग्रा), अंशिका (75 किग्रा), मेघा श्याकंद (80 किग्रा) और प्राची टोकस (+80 किग्रा) भी शामिल हैं। लड़कों की अंडर-19 टीम में ये खिलाड़ी शामिल हैं: लैलैनलकपाम अंबेकर मोतेई (50 किग्रा), आदित्य (55 किग्रा), सिक्कर (60 किग्रा), मौसम सुहाग (65 किग्रा), प्रशांत (70 किग्रा), देवेन्द्र चौधरी (75 किग्रा), लोकेश (80 किग्रा), सागर (85 किग्रा), शुभम राजपूत (90 किग्रा) और लावेन गुलिया (90+ किग्रा)।

हाल के कॉन्टिनेंटल और रोलबल इवेंट्स में अच्छे प्रदर्शन और कई वेट कैटेगरी में बढ़ती गहराई के साथ भारत इस चैंपियनशिप में उतर रहा है।

हम फेवरेट नहीं, बोस्निया और हर्जगोविना के खिलाफ मैच से पहले बोले अमेरिका के हेड कोच

सैन फ्रांसिस्को एजेंसी। अमेरिका के हेड कोच मौरिसियो पोचेतिनो ने कहा है कि उनकी टीम राउंड ऑफ 32 में होने वाले मुकाबले में हर संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अमेरिका का राउंड ऑफ 32 में बोस्निया और हर्जगोविना के खिलाफ मैच होगा। फीफा विश्व कप 2026 की सह-मेजबान अमेरिका ने पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया को हराकर ग्रुप डी में शीर्ष स्थान पर रहते हुए नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई किया था। मौरिसियो पोचेतिनो ने फीफा से बात करते हुए कहा, बोस्निया और हर्जगोविना एक बहुत ही जुझारू और आक्रामक टीम हैं। वे अच्छी तरह से व्यवस्थित भी हैं। जब आप मार्च में इटली के खिलाफ उनके ग्रुप-स्टेज मैच या



क्वालीफायर देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उनमें क्वालिटी है। उनके पास शानदार खिलाड़ी और कोच हैं, जो उन्हें प्रदर्शन करने के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं। अर्जेंटीना के पूर्व डिफेंडर ने यह भी बताया कि वह टूर्नामेंट शुरू होने से बहुत पहले से ही

शूटआउट की संभावना के लिए तैयारी पर भी काफी ध्यान दिया है।

उन्होंने कहा, अगर पेनल्टी की बात आती है तो हम तैयार रहेंगे। हमने उस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि यह वाकई जरूरी है। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हम इस पर काम कर रहे हैं क्योंकि, एक कोचिंग स्टाफ के तौर पर, हमारा मानना ​​​​है कि हम खिलाड़ियों को बेहतर होने के लिए टूल्स दे सकते हैं और उन्हें इस तरह के हालात से निपटने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढने में मदद कर सकते हैं पोचेतिनो ने कहा कि टूर्नामेंट के हाल के नतीजों से पता चला है कि नॉकआउट राउंड में कोई आसान विरोधी नहीं है। हम बोस्निया और हर्जगोविना का पूरा सम्मान करते हैं।

पोचेतिनो ने कहा कि उनके कोचिंग स्टाफ ने पेनल्टी

डीआर कांगो के कोच देसाब्रे को लगा एक और बड़ा झटका

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली पिता के निधन की खबर

अटलांटा एजेंसी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ राउंड ऑफ 32 में मिली हार के कुछ ही घंटों बाद कांगो डीआर के हेड कोच सेबेस्टियन देसाब्रे को निजी तौर पर एक और बड़ा झटका लगा है। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें अपने पिता के निधन की खबर मिली, जिसके बाद माहौल बेहद भावुक हो गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत समाप्त कर दी गई। नॉकआउट मुकाबले में डीआर कांगो ने इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी और शुरुआत में बेहतरीन खेल दिखाया। मैच के सातवें मिनट में ब्रायन सिंपेगा ने अपना पहला इंटरनेशनल गोल करते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि, इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने पहले बराबरी का गोल किया और फिर दूसरा और निर्णायक गोल कर अपनी टीम को 2-1 से जीत दिला दी। इस हार के साथ कांगो का ऐतिहासिक सफर राउंड ऑफ 32 में समाप्त हो गया। मैच के बाद जब कोच देसाब्रे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, तभी एक अधिकारी ने फ्रेंच भाषा में उनके पिता के निधन की सूचना दी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल पूरी तरह बदल गया। अधिकारी ने संवेदना व्यक्त करते हुए घोषणा की कि बातचीत समाप्त की जा रही है। शुरुआत में कोच को खबर पर यकीन नहीं हुआ। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने धीरे से धन्यवाद कहा और तुरंत उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले गए।

कांगो डीआर ने इस टूर्नामेंट में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। टीम ने अपने पहले फीफा वर्ल्ड कप में नॉकआउट चरण तक पहुंचकर इतिहास रचा। इससे पहले उन्होंने ग्रुप चरण में शानदार खेल दिखाते हुए



उज्बेकिस्तान को हराते हुए नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह बनाई थी। 1974 के बाद डीआर कांगो ने यह पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में डीआर कांगो ने अपने खेल से धरती की खासा प्रभावित किया।

हार के बाद कोच देसाब्रे ने कहा कि टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन अनुभव की कमी साफ तौर पर दिखी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने पूरी मेहनत की लेकिन आखिरी क्षणों में कुछ मौके गंवाना भारी पड़ा। उन्होंने कहा, हम निराश हैं क्योंकि हमें भरोसा था कि हम आगे जा सकते हैं। हमने अच्छा खेला लेकिन दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों ने से एक ने मौके का फायदा उठाया। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। देसाब्रे ने आगे कहा कि डीआर कांगो में फुटबॉल लगातार सुधार की ओर है और यह टीम के लिए सीखने का अनुभव है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी इस स्तर के मैच खेलकर और बेहतर बनेंगे और भविष्य में मजबूत वापसी करेंगे।

लिटन जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर, तौहीद संभालेंगे कमान

ढाका एजेंसी। जिम्बाब्वे के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच को पारी और 85 रन के अंतर से गंवाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान किया है। तौहीद हिरदोय को कप्तान नियुक्त किया गया है। लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) में अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण नियमित कप्तान लिटन दास, ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज, तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद और हसन महमूद इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। यह हिरदोय का टी20 अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तानी करने का दूसरा मौका होगा। इससे पहले उन्होंने पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मुकाबलों की घरेलू सीरीज में टीम की कमान संभाली थी, उस समय लिटन पिंडली की चोट के कारण उपलब्ध नहीं थे। नियमित कप्तान लिटन दास पिंडली की चोट से उबर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वे जिम्बाब्वे दौरे के दूसरे वनडे से पहले फिट हो जाएंगे। लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) का आयोजन 17 जुलाई से



8 अगस्त के बीच होगा। बांग्लादेश के चार खिलाड़ियों को एलपीएल में खेलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) दिया गया है।

डोड्डापनेनी कल्याण कृष्णा को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन में मिली बड़ी जिम्मेदारी



नई दिल्ली एजेंसी। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन (एसीए) ने बुधवार को बताया कि आंध्र के पूर्व तेज गेंदबाज डोड्डापनेनी कल्याण कृष्णा को राज्य का क्रिकेट ऑपरेशन्स का निदेशक बनाया गया है। मंगलगिरी में हुई एसीए की वार्षिक जनरल मीटिंग (एजीएम) में इस नियुक्ति को कन्फर्म किया गया। एसीए ने अपने बयान में कहा, एसीए हमारे क्रिकेट ऑपरेशन्स को मजबूत करने और इस क्षेत्र में खेल के लिए भविष्य के मजबूत विकास को आगे बढ़ाने में कल्याण कृष्णा के नेतृत्व का इंतजार कर रहा है। डोड्डापनेनी कल्याण कृष्णा ने आईएनएस से बात करते हुए अपनी नियुक्ति के लिए एसीए अध्यक्ष केसिनेनी शिवनाथ और सचिव सना सतीश बाबू को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा, मैं एसीए के अध्यक्ष और सचिव का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और यह भूमिका दी। मैं आंध्र टीम में एक खिलाड़ी के तौर पर था और अब मैं ऑफ-फील्ड रोल में टीम के साथ वापस आ गया हूँ। हर खिलाड़ी का सपना होता है

कि खेलने का समय खत्म होने के बाद वह खेल को कुछ वापस दे और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अब मैं ऐसा कर पा रहा हूँ।

कल्याण कृष्णा 2026/27 घरेलू सीजन की रणनीति बनाने के लिए आंध्र के हेड कोच गैरी स्टीड के साथ भी काम करेंगे।

उन्होंने कहा, यह मेरे लिए करियर में बदलाव जैसा है। मैंने अब तक कमेंटेटर के तौर पर अच्छी पहचान बनाई है और अब यह रोल निभाना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे यकीन है कि मैं इसके साथ पूरा न्याय करूंगा और एसीए द्वारा अब तक किए गए अच्छे काम को आगे बढ़ाऊंगा।

मेरी प्राथमिकताओं में राज्य में पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में खेल की पहुंच बढ़ाना और ऐसे और खिलाड़ी तैयार करना शामिल है जो आगे चलकर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें 42 साल के कल्याण कृष्णा ने आंध्र की तरफ से 51 प्रथम श्रेणी और 42 लिस्ट ए मैच खेले हैं। दाएं हाथ के इस गेंदबाज ने प्रथम श्रेणी में 154 और लिस्ट ए क्रिकेट में 52 विकेट लिए थे।

न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए बेन सियर्स



ऑकलैंड एजेंसी। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से पहले न्यूजीलैंड टीम को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज बेन सियर्स टखने की चोट के कारण पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। बेन सियर्स की जगह पर 16 सदस्यीय टीम में बेन लिस्टर को शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बताया कि सियर्स को मई में आयरलैंड के खिलाफ चार दिन के टेस्ट के बाद से टखने में लगातार दर्द हो रहा था, जो टेंट ब्रिज में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के आखिरी दिन और बढ़ गया। इसी कारण एतहाहास के तौर पर उन्हें इलाज के लिए न्यूजीलैंड भेजना का फैसला किया गया है। लिस्टर आने वाले दिनों में गुयाना में न्यूजीलैंड टीम के साथ मिलेंगे। 30 साल के मध्यम गति के तेज गेंदबाज लिस्टर ने 2023 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था। वह न्यूजीलैंड के लिए अब तक कुल 17 इंटरनेशनल मुकाबले (4 वनडे और 13 टी20) खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 17 विकेट निकाले हैं। वह अप्रैल में बांग्लादेश के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा रहे थे। न्यूजीलैंड की टीम अपने तेज गेंदबाजों की इंजरी से खासा परेशान है। सियर्स से पहले ब्लेयर टिकनर भी टखने की तय सर्जरी के कारण स्वेडिश लीट चुके हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं रहे थे। वहीं, जैकब डफी अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण इंग्लैंड में हाल ही में हुई टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाए थे। काइल जैमीसन, मैट हेनरी और विल ओरूक 2026 के पहले हाफ में वर्कलोड मेंनेज करने के लिए इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। पांच मैचों की सीरीज गुयाना में शुरू होगी, जिसके पहले तीन मैच 11, 13 और 16 जुलाई को होंगे, जिसके बाद सीरीज के आखिरी दो मैच 19 और 21 जुलाई को बारबाडोस के ब्रिजटाउन में होंगे।



महिला टी20 विश्व कप: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में खेलेंगी इंग्लैंड की कप्तान नट साइवर-ब्रंट

लंदन एजेंसी। महिला टी20 विश्व कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को मेजबान इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाना है। सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड के लिए अच्छी खबर यह है कि टीम की कप्तान नट साइवर-ब्रंट को फिट घोषित कर दिया गया है। साइवर-ब्रंट ने बुधवार को द ओवल में मैच से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लेइंग इलेवन में अपनी वापसी कन्फर्म करते हुए कहा, हमने सच में अपना सब कुछ झोक दिया। मैं शारीरिक रूप से जहां हूँ, उससे बहुत खुश हूँ। मेडिकल टीम खुश है। मैं पूरे गेम में हिस्सा ले पा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। साइवर-ब्रंट की वापसी से इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन को मजबूती मिली है। उनकी मौजूदगी से टीम को एक गेंदबाजी का विकल्प भी मिलता है, जिससे टीम में संतुलन आता है। साउथैम्पटन में आयरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान साइवर-ब्रंट रिटायर्ड हर्ट हो गई थीं। उससे पहले ब्रंट अप्रैल के

आखिर में घरेलू क्रिकेट खेलते समय इंजर्ड हो गई थीं और इस वजह से भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज नहीं खेल पाई थीं। ब्रंट ने टूर्नामेंट से पहले दोनों वार्म-अप मैच खेले थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 3, जबकि भारत के खिलाफ 57 रन बनाए थे। इसके बाद वर्ल्ड कप में श्रीलंका और आयरलैंड के खिलाफ क्रमशः 46 और 48 रन बनाए। इंग्लैंड अपने सभी पांच ग्रुप मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है। कप्तान नट साइवर-ब्रंट की वापसी से पहले से ही मजबूत टीम और भी बेहतर हो गई है। इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत-हॉक टॉप ऑर्डर है, जिसे टूर्नामेंट की टॉप रन-स्कोरर डैनी वायट-उनॉज लीड कर रही हैं। अनुभवी ओपनर ने पांच पारियों में 94 की औसत से 282 रन बनाए हैं। इसमें द ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 89 रन की पारी शामिल है। उन्हें पहले ही तीन प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिल चुके हैं।

वन विभाग की बड़ी कार्रवाई : दो बाघ की खाल के साथ दो तरकर गिरफ्तार



मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के निर्देशन में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग की संयुक्त टीम ने दो बाघों की खाल के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई कांकेर जिले के पश्चिम भानुप्रतापपुर स्थित बांदे परिक्षेत्र में छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर गोपनीय सूचना के आधार पर की गई। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले के निवासी व्येश्वर और बाबुराव के रूप में हुई है। दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से अनुसूची-1 में शामिल संरक्षित वन्यजीव बाघ की दो खालों की अवैध तस्करी कर रहे थे। संयुक्त टीम ने उन्हें रो हाथ पकड़ लिया। इस कार्रवाई में वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) के उत्तरी एवं मध्य क्षेत्र, राज्य उड़नदस्ता दल (छत्तीसगढ़ वन विभाग), एंटी पोनिंग यूनिट (यूएसटीआर) तथा स्थानीय वन अमले ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया।

अन्य आरोपियों की तलाश जारी: वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई जारी है तथा जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किए जाने की संभावना है।

वन्यजीव संरक्षण के प्रति सरकार की सख्ती: छत्तीसगढ़ सरकार वन्यजीव संरक्षण और वन्यजीव की अवैध तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। वन विभाग द्वारा विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित निगरानी और संयुक्त अभियान संचालित किए जा रहे हैं, जिससे वन्यजीवों के संरक्षण को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वन विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहा है।

नगर पंचायत बम्हनीडीह के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह कल

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। जांजगीर-चांपा जिले के नगर पंचायत बम्हनीडीह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 2 जुलाई 2026, गुरुवार को प्रातः 10:30 बजे आई.टी.आई. ग्राउंड, बम्हनीडीह में आयोजित किया जाएगा। समारोह में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री रमेश कुमार डड्डेसना तथा सभी नवनिर्वाचित पार्षद पद एवं गोपनीयता की शपथ लेगे। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव करेंगे। जिले के प्रभारी मंत्री एवं वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब तथा जांजगीर-चांपा सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंहदेव, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह, जैजैपुर विधान सभा बालेश्वर साहू, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल, पूर्व संसदीय सचिव श्री अम्बेश जांगड़े तथा जिला पंचायत जांजगीर-चांपा की अध्यक्ष इजी. सत्यलता आनंद मिरी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं क्षेत्रवासियों की उपस्थित रहेंगे।

रेत की अवैध तस्करी पर वन विभाग का बड़ा प्रहार, 12 ट्रैक्टर जळ



मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा वन संपदा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने रेत की अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत से लदे 12 ट्रैक्टर जळ किए हैं। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत बैहामुड़ा के पास स्थित कुरकुट नदी से लंबे समय से अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा था। तस्करी ने वन क्षेत्र के भीतर घने जंगल से होकर एक गुप्त रास्ता तैयार कर लिया था, जिससे वे मुख्य सड़क और जांच चौकियों से बचते हुए रेत का परिवहन कर रहे थे। सूचना मिलते ही वनमंडलाधिकारी श्री अरविंद पी. एम. के निर्देशन, उप वनमंडलाधिकारी श्री आशुतोष मांडवा के मार्गदर्शन तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री विक्रंत कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाया। वन अमले ने जंगल के विभिन्न हिस्सों में घेराबंदी कर बिना वैध अनुमति और बिना परिवहन पास के रेत का परिवहन कर रहे 12 ट्रैक्टरों को मौके पर ही जळ कर लिया।

'वन अपराध का प्रकरण दर्ज, होगी सख्त कार्रवाई': कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम को देखकर कई तस्करी गैके से भाग निकले, लेकिन विभाग ने रेत से लदे सभी ट्रैक्टर अपने कब्जे में ले लिए। जळ वाहनों को घरघोड़ वन परिक्षेत्र कार्यालय लाकर आवश्यक जांच और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। वन विभाग ने इस मामले में भारतीय वन अधिनियम के तहत वन अपराध का प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

'वन संपदा के संरक्षण के लिए अभियान रहेगा जारी': वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन क्षेत्र में अवैध खनन, रेत तस्करी और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार वन संपदा की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बस्तर संभाग की शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की शिक्षा गुणवत्ता सुधारने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)।

शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने आज बुधवार को बस्तर कलेक्टोरेट के प्रेरणा सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर विभागीय योजनाओं एवं शैक्षणिक गतिविधियों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि बस्तर के समग्र विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अंदरूनी क्षेत्रों के स्कूलों को पुनर्जीवित करने, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने तथा विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण विकसित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने प्राथमिक स्तर पर गणित, हिंदी और अंग्रेजी की मजबूत आधारशिला तैयार करने के लिए कैलेंडरवार, शालावार एवं विषयवार समय-सारणी के अनुसार पढ़ाई कराने तथा नियमित रिवीजन टेस्ट आयोजित करने के निर्देश दिए।बैठक में शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, संचालक श्री ऋतुराज रघुवंशी, कलेक्टर श्री आकाश छिक्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रतीक जैन, संभागीय संयुक्त संचालक श्री एच.आर. सोम सहित सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, डीएमसी, बीईओ एवं अन्य अधिकारी



उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान आधार बेस ऐप के माध्यम से कार्यालयीन अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति तथा वीएसके ऐप में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की जानकारी ली गई। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा नेटवर्क विहीन स्कूलों की सूची कलेक्टर के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। शिक्षा मंत्री ने अन्य विभागों में पदस्थ

शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को मूल पदस्थापना पर वापस भेजने संबंधी निर्देशों के पालन की भी समीक्षा की। श्री यादव ने बसाहटवार प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति, नए विद्यालयों की आवश्यकता, बंद स्कूलों को पुनः प्रारंभ करने की कार्ययोजना, बोर्ड एवं वार्षिक परीक्षा परिणामों की समीक्षा करते हुए पोटा विहीन स्कूलों की सूची कलेक्टर के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वार्षिक परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए पिछले

वर्षों के प्रश्नपत्रों के आधार पर विषयवार यूनिट टेस्ट एवं तिमाही परीक्षाएं आयोजित करने तथा कमजोर विद्यालयों के प्राचायों की बैठक लेकर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जिला एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को दिए।बैठक में विद्यार्थियों के नामांकन, उपस्थिति, ड्रापआउट की स्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता, रिक्त एवं युक्तियुक्तकरण किए गए पदों, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों की कार्ययोजना एवं गैप

एनालिसिस की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

छात्रवृत्ति, गणवेश, पाठ्यपुस्तक वितरण, सरस्वती सायकल योजना, मध्याह्न एवं न्यौता भोजन, निर्माण कार्यों तथा शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। शिक्षा मंत्री श्री यादव ने स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों को पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर विकसित करने, जर्जर विद्यालय भवनों को नियमानुसार ध्वस्त कराने, विद्यालयों की आवश्यक मरम्मत एवं छोटे कार्यों में उपलब्ध बजट का उपयोग करने तथा पाठ्यपुस्तकों का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अतिरिक्त पुस्तकों का संकूल एवं विद्यालय स्तर पर व्यवस्थित रिकार्ड संचारित करने पर भी जोर दिया। अधिकारियों ने बैठक में संभाग में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों एवं योजनाओं की प्रगति से मंत्री को विस्तारपूर्वक अवगत कराया।बैठक से पूर्व शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कलेक्टोरेट परिसर में सरस्वती सायकल योजना के अंतर्गत पात्र छात्राओं को निःशुल्क सायकल एवं उपहार वितरित किए तथा उन्हें मेहनत, लगन और नियमित अध्ययन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

डिजिटल व्यवस्था से आसान हुई सरकारी सेवाओं तक पहुंच

सेवा सेतु’ ने दी राहत, कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना समय पर मिला आय प्रमाण-पत्र

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)।

शासन की जनहितकारी पहल ‘सेवा सेतु’ आम नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की सहज, सरल और समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित कर रही है। डिजिटल माध्यम से संचालित इस व्यवस्था ने वर्षों से चली आ रही अनावश्यक भागदौड़ और लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को काफी हद तक सरल बना दिया है। अब नागरिकों को आवश्यक प्रमाण-पत्रों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि निर्धारित समय-सीमा में पारदर्शी तरीके से सेवाओं का लाभ मिल रहा है।कोराबा के कटघोरा तहसील के ग्राम राल निवासी श्री रामेश्वर कंवर को अपने पुत्र हिमाचल सिंह एवं पुत्री देवांशी कंवर के लिए आय प्रमाण-



पत्र की आवश्यकता थी। उन्होंने संचालित हुई और उन्हें किसी भी कार्यालय के अनावश्यक चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ ही दिनों में उनके दोनों बच्चों

के आय प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए।श्री रामेश्वर कंवर ने बताया कि ‘सेवा सेतु’ के माध्यम से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया बेहद सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक रही। उन्हें समय पर प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ, जिससे उनके समय और संसाधनों दोनों की बचत हुई। उन्होंने कहा कि ‘सेवा सेतु’ जैसी डिजिटल व्यवस्था से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिल रही है तथा शासन की सेवाओं के प्रति लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो रहा है।‘सेवा सेतु’ के माध्यम से शासन का उद्देश्य नागरिकों को पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह पहल सुशासन, डिजिटल प्रशासन और जन केंद्रित सेवा वितरण की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रही है।

मंत्री श्री नेताम ने किया कृषि महाविद्यालय कुरुद का भ्रमण, आधुनिक शिक्षण एवं अनुसंधान सुविधाओं का लिया जायजा

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज बस्तर प्रवास के दौरान कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कुरुद का भ्रमण कर महाविद्यालय में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्यों तथा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने आधुनिक कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को

राज्य के कृषि विकास की मजबूत आधारशिला बताते हुए विद्यार्थियों को नवाचार और तकनीक आधारित कृषि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय पहुंचने पर अधिष्ठाता डॉ. नवनीत राणा ने मंत्री श्री नेताम का स्वागत किया तथा विभिन्न शैक्षणिक एवं अनुसंधान गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। मंत्री श्री नेताम ने निरीक्षण किया। उन्होंने आधुनिक प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लासरूम,

डिजिटल लाइब्रेरी और कॉम्प्यूटिस्टिव फोरम का निरीक्षण किया तथा छात्र-छात्राओं से संवाद कर महाविद्यालय एवं छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें अध्ययन एवं आवास से जुड़ी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। भ्रमण के दौरान मंत्री श्री नेताम ने कृषि संग्रहालय में छात्र-छात्राओं द्वारा तैयार कृषि मॉडल, प्रदर्शनी और मशरूम प्रसंस्कृत उत्पादों का अवलोकन किया।

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर किया आत्मीय स्वागत, न्यौता भोज में साथ में किया भोजन

शाला प्रवेशोत्सव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक सुविधाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर दिया गया जोर

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)।

केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू तथा उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज बिलासपुर में सेजेंस लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर स्थित देवकीनंदन दशित सभागार में जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कर आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने नए शिक्षा सत्र के शुभारंभ पर विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने, संस्कारवात नागरिक बनने और अपने माता-पिता, गुरुजनों तथा प्रदेश का नाम रोशन करने का संदेश दिया। अतिथियों ने बच्चों के साथ न्यौता भोज में शामिल होकर भोजन किया। कार्यक्रम में छात्राओं को सरस्वती सायकल योजना के तहत सायकल का वितरण भी किया गया। विधायक श्री सुराशत शुक्ला, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री राजा पांडे, महापौर श्रीमती पूजा विधानी और जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी भी शाला प्रवेशोत्सव में शामिल हुए। शाला प्रवेशोत्सव शिक्षा के प्रति समाज की सामूहिक जिम्मेदारी का उत्सव है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसकी प्राथमिक पाठशाला की



: श्री तोखन साहूबतौर मुख्य अतिथि के केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं पालकों को नए शिक्षा सत्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शाला प्रवेशोत्सव केवल कार्यक्रम नहीं, बल्कि शिक्षा के प्रति समाज की सामूहिक जिम्मेदारी का उत्सव है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसकी प्राथमिक पाठशाला की

स्मृतियां हमेशा बनी रहती हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छे संस्कार और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों से पूरे मन से अध्ययन कर अपने परिवार, समाज, प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया।कड़ी मेहनत और शिक्षा ही सफलता का सबसे बड़ा आधार : श्री अरुण सावकार्यक्रम की

अध्यक्षता कर रहे उप मुख्यमंत्री तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार विद्यालयों में सुविधाओं का विस्तार कर रही है। आज स्कूलों में भवन, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि यदि जीवन में सम्मानपूर्वक आगे बढ़ना है तो कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। विद्यार्थियों को पूरे समर्पण के साथ पढ़ाई कर अपने सपनों को साकार करना चाहिए। उन्होंने बच्चों से अपनी प्रतिभा से पूरे देश में राज्य का गौरव बढ़ाने की अपील की।

स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित हों : श्री सुराशत शुक्ला:विधायक श्री सुराशत शुक्ला ने कहा कि विद्यार्थियों का सामाजिक आँडिट होना चाहिए, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सभी आवश्यक सुविधाएं मिलना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि कोई भी विद्यालय शौचालयविहीन, जर्जर या अवैध कब्जे से प्रभावित नहीं होना चाहिए। विद्यालयों का

भेजेन की अपील की गई।इस अवसर पर छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों, मध्याह्न भोजन सहित शासन द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही बालिकाओं को नियमित अध्ययन, विद्यालय में सतत उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पर्ववैशकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, किशोरी बालिकाओं, उनके अभिभावकों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजनों की सहभागिता रही।



परियोजना बलौदा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान स्कूल चलो अभियान के तहत बालिकाओं को नियमित रूप से विद्यालय जाने के लिए प्रेरित किया गया। अभिभावकों से बालिकाओं की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्हें नियमित रूप से स्कूल

भेजेन की अपील की गई।इस अवसर पर छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों, मध्याह्न भोजन सहित शासन द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही बालिकाओं को नियमित अध्ययन, विद्यालय में सतत उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पर्ववैशकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, किशोरी बालिकाओं, उनके अभिभावकों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजनों की सहभागिता रही।